साध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए... क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं.....!!

अज्ञात...

वर्ष-01 अंक-200 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शनिवार 08 अगस्त 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए

राहुल गांधी बोले- कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे फेवरेट बीजेपी लीडर

मुस्कुराते हुए हैलो अंकल अमरिंदर कहा, पंजाब कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज

नई दृष्टिबिंदु / नई दिल्ली।

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी. के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री .कैप्टन अमरिंदर सिंह. को अपना ह्यफेवरेट इखढ लीडरह्ल बता दिया।

जेन-जी से बातचीत में किया जिक्र

गुरुवार को दिल्ली में राहुल गांधी ने जेन-जी युवाओं के साथ इंट्रैक्शन किया। इसी दौरान एक युवा ने उनसे पूछा कि "बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है?" इस पर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया "कैप्टन अमरिंदर सिंह, डेफिनेटली। मैं उनके साथ आसानी से घुल-मिल जाता हूं। वह कूल हैं और मिलिट्री हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं उन्हें पसंद करता हूं। हैलो अंकल अमरिंदर... राहुल गांधी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट किया है।

कांग्रेस को मिस करता हूं बोले थे कैप्टन

राहुल के बयान के बाद से ही पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन हाल ही में उन्होंने खुद कहा था कि

."वह कांग्रेस को मिस करते हैं। कांग्रेस एक फैमिली की तरह है। मैं जब भी फोन करता था, वह मिल लेते थे। मगर, भाजपा में ये सिस्टम नहीं है। कैप्टन ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी ने उनके चचेरे भाई के निधन पर शोक संदेश भेजा, लेकिन भाजपा में किसी ने पूछा तक नहीं।

पंजाब कांग्रेस में खलबली

Gen-z का असंतोष : संघ-भाजपा के लिए 'System Correction' की चुनौती

आलोक तिवारी
विश्लेषण

मोहन भागवत का बदला सुर, विपक्ष ने पूछे सवाल

नई दृष्टिबिंदु / नई दिल्ली

देश में छात्रों और Gen-Z की नाराजगी अब सत्ता के सबसे ऊपरी गलियारों तक पहुंच चुकी है। जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन और सोशल मीडिया पर मीम्स, रील्स के जरिए बन रहा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए 2014 के अन्ना आंदोलन जैसी चुनौती बनता दिख रहा है।

सुर बदला: विरोध नहीं तकलीफ है

पिछले कुछ हफ्तों में जब छात्र आंदोलन तेज हुए तो सत्तापक्ष के कुछ नेताओं के तीखे बयानों ने माहौल और गरमा दिया। आरोप लगा कि आंदोलन को "राष्ट्रविरोधी" या "असामाजिक" खांचे में डालने की कोशिश हुई।

लेकिन अब शीर्ष नेतृत्व की भाषा बदली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पीढ़ी के संवाद के नए तरीके — मीम्स और रील्स — को समझने की बात की। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत ने Gen-z के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया।

भागवत का बयान सबसे अहम रहा

अगर Gen-z चिल्ला रही है, तो वह केवल विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, बल्कि उसे कोई तकलीफ है। आंदोलन System Correction के लिए होना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि केवल लगातार चुनाव जीतना ही अच्छे नेतृत्व की पहचान नहीं है।

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह बयान सत्ता पक्ष के भीतर इस बात की स्वीकारोक्ति है कि युवाओं का गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा और भविष्य को लेकर गहरी बेचैनी से जुड़ा है।

विपक्ष का पलटवार: अब क्यों याद आई तकलीफ?

संघ प्रमुख के इस नरम रुख पर कांग्रेस और विपक्ष ने तुरंत हमला किया। राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं का सवाल है कि जब छात्रों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज हो रहा था तब चुप्पी क्यों थी?

विपक्ष का आरोप है कि यह "भाषा बदलने" की कवायद है, "नीति बदलने" की नहीं। उनका कहना है कि सरकार को आंदोलन के मूल कारणों — पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा का महंगापन — पर ठोस कदम उठाने होंगे।

Gen-z फैक्टर: 2014 जैसा मोड़?

2014 में वढअ-2 के खिलाफ अन्ना आंदोलन और भ्रष्टाचार के मुद्दे ने सत्ता समीकरण बदल दिए थे। इस बार Gen-z का विरोध डिजिटल है, विकेंद्रित है और किसी एक नेता के इर्द-गिर्द नहीं है। यही इसे सत्ता के लिए ज्यादा जटिल बनाता है।

भाजपा और संघ के लिए चुनौती यह है कि वे इस असंतोष को "एंटी-नेशनल" कहकर खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि यह वोटर बेस का बड़ा हिस्सा है। इसलिए "System Correction" जैसे शब्दों के जरिए संवाद की कोशिश हो रही है।

संसद में भी दिखी असुविधा

इसी बीच दिल्ली की मूसलाधार बारिश ने नई संसद भवन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। पोटिकी न होने के कारण राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अमित शाह तक को छतरी लेकर प्रवेश करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उढहऊ को पुराने संसद की तरह पोटिकी बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रतीकात्मक रूप से यह भी दिखाता है कि नई व्यवस्थाओं को जमीनी हकीकत के हिसाब से ढालना जरूरी है।

आगे क्या?

फिलहाल सत्ता पक्ष संवाद और सहानुभूति की भाषा अपना रहा है, जबकि विपक्ष इसे अवसर मानकर छात्रों के साथ खड़ा दिख रहा है। त्रीह्ल- का यह दबाव आने वाले महीनों में शिक्षा, रोजगार और युवा नीतियों पर सरकार के रुख को तय करेगा।

शराब दुकानों में गड़बड़ी पर आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन

दो उपनिरीक्षक निलंबित, सहायक जिला आबकारी अधिकारी पर हुई कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में अधिक कीमत पर बिक्री और अन्य अनियमितताओं के मामलों में आबकारी विभाग ने एक ही दिन तीन बड़ी कार्रवाई. की है। विभाग ने बलौदाबाजार-भाटापारा और बालोद के .दो आबकारी उपनिरीक्षकों. को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि .53 पेटी अवैध शराब प्रकरण. में बालोद की सहायक जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा शासन को भेजी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा - जीरो टॉलरेंस की नीति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय. ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी या कमर्चारी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

ये हैं मामले.

बलौदाबाजार-भाटापारा रोहासी देशी कम्पोजिट शराब दुकान में अधिक कीमत पर शराब बिक्री की शिकायत मिली थी। मूल शिकायत के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने और दुकान के .सीसीटीवी सिस्टम को अद्यतन नहीं रखने. के कारण आबकारी उपनिरीक्षक .पी. माधव राव. को निलंबित किया गया है। बालोद-धमतरी.: 25 जुलाई को धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में .53 पेटी अवैध देशी एवं विदेशी शराब. जब्त की गई थी। जांच में होलोग्राम के आधार पर शराब का स्रोत बालोद जिले की .अरकार देशी कम्पोजिट शराब दुकान. पाया गया। निर्धारित सीमा से अधिक थोक बिक्री सामने आने पर संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक .आशा राम शाक्य. को निलंबित किया गया है। इसी प्रकरण में अरकार दुकान की प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी .निलोफर जैन. के शिथिल नियंत्रण और कर्तव्य के प्रति लापरवाही को गंभीर मानते हुए आबकारी आयुक्त ने उनके विरुद्ध नियमानुसार .अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को भेज दी है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अधिक मूल्य पर बिक्री अथवा नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

JPSC-JSSC विवाद | 14वें दिन हेमंत सरकार से छात्रों की पहली वार्ता, माहौल सकारात्मक

आंदोलनकारी छात्र की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में किया गया भर्ती

नई दृष्टिबिंदु / राँची।

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर पिछले 14 दिनों से जारी छात्रों का अनशन और आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ते दबाव के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने राँची में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से पहली आधिकारिक वार्ता की।

राँची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र पिछले दो हफ्तों से आमरण अनशन और धरना दे रहे हैं। शुक्रवार को सरकार के साथ हुई बैठक के बाद बाहर आए छात्र प्रतिनिधियों ने बताया कि वार्ता का माहौल सकारात्मक और सौहादर्पूर्ण रहा। सरकार ने उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। शुरुआत में सरकार ने छात्रों के साथ आए मार्गदशकों यानी वकीलों और पत्रकारों की उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद केवल 10 छात्र प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए भेजा गया। अनशनकारी छात्र की बिगड़ी तबीयत, ओलंपिक चैंपियन के बेटे ने दिया समर्थन.

अनशन के 14वें दिन सुबह करीब 9 बजे अनशनकारी छात्र राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आनन-फानन में राँची जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंदोलन को समर्थन देने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हॉकी दिग्गज जयपाल सिंह मुंडा के छोटे बेटे जयंत जयपाल सिंह भी स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने कहा कि युवाओं की यह नई लहर राज्य में भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सिस्टम की गंदगी को साफ करेगी।

मुख्यमंत्री बोले- दरवाजे खुले हैं

प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि "छात्रों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम वार्ता के लिए तैयार हैं और छात्रों की समस्या को हल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।"

संसद से लेकर संघ तक गूंजा मामला.

दिल्ली में संसद के मानसून सत्र में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और गृह मंत्री अमित शाह से सदन में जवाब देने की मांग की। इस बीच फ्रर प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि Gen को एंटी-नेशनल कहना गलत है, आंदोलन करना उनका अधिकार है।" इस पर विपक्षी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि जब छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही थीं, तब संघ प्रमुख कहाँ थे? अब सभी की नजर सरकार और छात्रों के बीच होने वाली अगली वार्ता और उसमें निकलने वाले ठोस नतीजों पर टिकी हैं।

आंदोलन का समर्थन करने पहुंचीं नेहा बोरा पर स्याही फेंकी

नई दृष्टिबिंदु / रांची

झारखंड में छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचीं एक्टिविस्ट .नेहा बोरा. पर गुरुवार को रांची में स्याही फेंकने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद राजनीतिक और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल के कुछ लोगों द्वारा यह आलोचना की जा रही थी कि नेहा बोरा अभी तक झारखंड के छात्रों के आंदोलन में शामिल नहीं हुई हैं। इस आलोचना के बीच नेहा बोरा रांची पहुंचीं और छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होकर उनका समर्थन किया। झारखंड के छात्रों ने उनका स्वागत भी किया। छात्र आरक्षण, जाति जनगणना और यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेहा बोरा इन मुद्दों की समर्थक रही हैं।

रांची में कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति नेहा

बोरा पर स्याही फेंक दी। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर आरोपी ने कहा कि नेहा बोरा ह्यटुकड़े-टुकड़े गैंगह्ल का हिस्सा हैं। टुकड़े-टुकड़े गैंग शब्द पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक बहसों में इस्तेमाल होता रहा है।

नेहा बोरा के समथर्कों की प्रतिक्रिया

घटना के बाद नेहा बोरा के समथर्कों ने इसकी निंदा की है। समथर्कों का कहना है कि नेहा बोरा के माता-पिता बीजेपी के समर्थक हैं और वे खुद आरक्षण, जाति जनगणना और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाती हैं। उन्होंने कहा कि असहमति के बावजूद इस तरह की हरकत लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और नेहा बोरा को समर्थन दिया जाना चाहिए।

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

"डीजीपी पूरी तरह अयोग्य" : जेल में मौत की रिपोर्ट

2 साल दबाने पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, CBI जांच का दिया संकेत, छत्तीसगढ़ पुलिस-गृह विभाग कठघरे में

नई दृष्टिबिंदु / नई दिल्ली।

छत्तीसगढ़ में न्यायिक हिरासत में हुई मौत और उसकी जांच रिपोर्ट को दो साल तक दबाए रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस और शासन के शीर्ष अधिकारियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। 4 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने छत्तीसगढ़ डीजीपी की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पूरे महकमे की जवाबदेही पर सवाल उठाए।

.क्या है पूरा मामला.

बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम मोहरा से 18 जनवरी 2024 को श्रवण सूर्यवंशी को 6 लीटर कच्ची महुआ शराब रखने के आरोप में आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। 19 जनवरी को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे बिलासपुर केंद्रीय जेल भेजा गया। जेल में तबीयत बिगड़ने पर उसे सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां 22 जनवरी 2024 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

तत्कालीन जेएमएफसी नसन डेविड लकड़ा द्वारा की गई न्यायिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मौत सिर में किसी कुंद वस्तु से लगी चोट और उसकी जटिलताओं के कारण हुई थी।

2 साल तक कहां अटकी रही रिपोर्ट

मामले का सबसे गंभीर पहलू रिपोर्ट को दबाने से

जुड़ा है। 5 अगस्त 2024 को बिलासपुर जेएमएफसी की न्यायिक जांच रिपोर्ट जेल अधीक्षक के पास पहुंच गई थी। लेकिन इसे पुलिस तक पहुंचने में लगभग दो साल लग गए। 28 जुलाई 2026 को जेल विभाग ने रिपोर्ट पुलिस को भेजी और 30 जुलाई 2026 को सिविल लाइन थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज हुई।

हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक

मृतक की पत्नी लहराबाई और दो बेटियों ने हाई कोर्ट में निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की। हाई कोर्ट ने ₹50 लाख के बदले 1 लाख रुपये मुआवजा दिया। इससे असंतुष्ट होकर परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में रछ्ढ दायर की।

सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

4 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी अरुण देव गौतम, गृह सचिव निहारिका बारिक और डीजी जेल हिमांशु गुप्ता पेश हुए। सुनवाई में कोर्ट ने कहा:

1. "हमें यह कहते हुए खेद है कि हमें रिकॉर्ड पर यह दर्ज करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी पूरी तरह अयोग्य हैं।"
2. जब न्यायिक जांच में सिर पर गंभीर चोट से मौत दर्ज थी, तब भी पुलिस का यह कहना कि संज्ञेय अपराध नहीं बनता, अदालत को गुमराह करना है।
3. कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस से लेकर किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे उइकको सौंपी जानी चाहिए।

अब सवाल: जवाबदेही किसकी.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गृह और पुलिस विभाग में हड़कंप है। दो साल तक न्यायिक जांच रिपोर्ट दबाने और देरी से हत्या का मामला दर्ज करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे की मांग दोहराई है। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट स्वतंत्र एजेंसी से जांच पर फैसला ले सकता है।

'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र -2026' के तहत बीएसपी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बनाई 2500 राखियां

सीमा पर तैनात सैनिकों को ससम्मान सौंपे गए रक्षा सूत्र, मिट्टी और संदेश-पत्र

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से .पूर्व सैनिक महासभा एवं सिपाही संगठन. द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी अभियान .'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 0.4, 2026'. के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों ने लगभग .2500 रक्षा सूत्र (राखियां). तैयार कर सैनिकों को समर्पित कीं। विद्यार्थियों ने अत्यंत श्रद्धा और स्नेह के साथ इन राखियों को बनाया। इसके साथ ही सैनिकों के तिलक के लिए .चुटकी भर पवित्र मिट्टी. और उनके नाम .सम्मान व शुभकामनाओं से भरे संदेश-पत्र. भी तैयार किए गए।

इन सभी सामग्रियों को सीमा पर तैनात जवानों तक पहुंचाने के लिए .5 अगस्त 2026 को अपराह्न 3 बजे घड़ी चौक, सुपेला. में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम .स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ, भिलाई. के तत्वावधान में हुआ, जहां सभी सामग्री संग्रहण समूह को ससम्मान सौंपी गई।

उल्लेखनीय है कि स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ, भिलाई पिछले .4 वर्षों से लगातार. इस अभियान के माध्यम से रक्षा सूत्र देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों तक भेज रहा है। यह पहल विद्यार्थियों में .राष्ट्रप्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व और सैनिकों के प्रति सम्मान. की भावना विकसित करने की दिशा में एक प्रेरणादायी प्रयास है।

पदाधिकारी और विद्यार्थी रहे उपस्थित.

कार्यक्रम जिला मुख्य आयुक्त, स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ, भिलाई और महाप्रबंधक (शिक्षा-टीएसडी) .शिखा दुबे. के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्काउट्स एवं गाइड्स के पदाधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षकगण सहित बड़ी संख्या में स्काउट्स, गाइड्स और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

खास खबर

निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु मंडल की बैठक में अहम फैसले

नई दृष्टिबिंदु /रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कमकार कल्याण मंडल की पंचम कायर्काल की नवम बैठक आज नवा रायपुर स्थित मंडल कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री *लखनलाल देवांगन. ने की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष .डॉ. रामप्रताप सिंह., उप सचिव श्रम विभाग .विपुल गुप्ता., अपर श्रमायुक्त .एस.एल. जांगड़े., कल्याण प्रशासक .सुनील मिश्रा., मंडल सचिव .गिरीश रामटेके. सहित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा और कोचिंग के लिए बड़े निर्णय

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना.: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के 20 चयनित विद्यालयों में 200 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6वीं में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। उच्च शिक्षा में सहायता राशि का एकरूपीकरण.: इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली शैक्षणिक सहायता राशि का एकरूपीकरण करने का निर्णय लिया गया। इससे अधिक पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अटल करियर निर्माण योजना.: 2026-27 में 1,000 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को .ठएएळ और खएए. जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया।

सुरक्षा को मजबूती.

बैठक में नवीन .सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020. के अनुरूप श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भी निर्णय लिया गया। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचे। मंडल अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि श्रमिकों के हित में नई योजनाएं शुरू करने के साथ-साथ वतर्मान योजनाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।

सीएसवीटीयू के इंडक्शन प्रोग्राम में कनाडा के प्रो. गजपाल ने दिए शैक्षणिक सफलता के टिप्स

विदेशों में उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर दिया जोर

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कुलपति प्रो. (डॉ.) अरुण अरोरा के मार्गदर्शन में हुआ।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, पाठ्यक्रम, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, परीक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और छात्र कल्याण योजनाओं से परिचित कराना था, ताकि वे अपने शैक्षणिक जीवन की सकारात्मक शुरुआत कर सकें।

कार्यक्रम में कुलपति प्रो. (डॉ.) अरुण अरोरा, कुलसचिव डॉ. अमित सिंह राजपूत और यूटीडी निदेशक डॉ. पंकज मिश्रा ने विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तकनीकी ज्ञान के साथ अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

इंडक्शन प्रोग्राम के तहत कनाडा के मॉनिटोबा विश्वविद्यालय, विनिपेग स्थित एस्पर स्कूल ऑफ बिजनेस के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विभाग के प्रोफेसर डॉ. युवराज गजपाल ने "शैक्षणिक सफलता की प्राप्ति : कौशल विकास" विषय पर व्याख्यान दिया।

डॉ. गजपाल ने कहा कि वतर्मान प्रतिस्पर्धी दौर में केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। तार्किक क्षमता, व्यावहारिक ज्ञान, आत्ममूल्यांकन, संचार कौशल, समस्या-समाधान क्षमता और निरंतर कौशल विकास भी सफलता के लिए जरूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ से कनाडा तक की अपनी यात्रा साझा करते हुए विद्यार्थियों को दृढ़ संकल्प और योजनाबद्ध तैयारी का संदेश दिया। विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रतियोगी और भाषा दक्षता परीक्षाओं, शोध आधारित पीजी-पीएचडी कार्यक्रमों और छात्रवृत्ति के अवसरों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने सलाह दी कि विद्यार्थी तीसरे वर्ष से ही उच्च शिक्षा और करियर के लक्ष्यों के लिए तैयारी शुरू कर दें। व्याख्यान के दौरान विद्यार्थियों ने विदेश में पढ़ाई, शोध और करियर को लेकर सवाल पूछे, जिनका डॉ. गजपाल ने विस्तार से जवाब दिया।

कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. शिवांगी चंद्राकर और शेष नारायण साहू रहे। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. आर. जी. ब्रजेश ने किया। मंच संचालन नेहा पटनायक और अपूवर्धारा नाग ने किया। इस अवसर पर डॉ. जे. पी. पात्रा, डॉ. तोरण वर्मा, डॉ. मनीष कुमार सिन्हा, डॉ. आशीष शर्मा सहित विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, अधिकारी, कमर्चारी और बड़ी संख्या में नवप्रवेशी विद्यार्थी उपस्थित थे।

दुर्ग जिले का उभरता सितारा : 19 वर्षीय अभियांश सिंह चौहान ने एनसीएल में किया धमाल

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग जिले के 19 वर्षीय युवा क्रिकेटर *अभियांश सिंह चौहान. ने अपनी मेहनत और प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज और मध्यम गति के तेज गेंदबाज अभियांश का चयन .नेशनल क्रिकेट लीग भारत (NCL). के लिए हुआ है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से संबद्ध नेशनल क्रिकेट लीग भारत ने देश के 29 राज्यों में ट्रायल आयोजित किए थे। पूरे भारत से लगभग .2000 खिलाड़ियों. ने भाग लिया। अभियांश ने .बिहार के पटना. में ट्रायल दिया और .1000 चयनित खिलाड़ियों. में अपनी जगह बनाई।

इसके बाद .नोएडा क्रिकेट स्टेडियम. में हुए 3 टी-20 मैचों में अभियांश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए .150 रन और 5 विकेट. लिए। इसी प्रदर्शन के आधार पर वे .500 में से 500 चयनित खिलाड़ियों. में शामिल हुए।

इसके बाद .गोवा में 3 दिवसीय फिटनेस शिविर. लगा। यहां प्रदर्शन के आधार पर मुख्य टूर्नामेंट की नीलामी के लिए .500 में से सिर्फ 90 खिलाड़ियों. का चयन किया गया।

.मजबूत बाघों ने 2000 में खरीदा.

नीलामी में सभी 90 खिलाड़ियों की बोली लगी। अभियांश को .टीम मजबूत बाघों. ने .?2000. में खरीदा। एनसीएल में नए होने के कारण उन्हें इस राशि का चेक मिला।

मुख्य टूर्नामेंट में अभियांश ने कप्तानी भी की। उन्होंने .2 मैचों में 100 रन और 2 विकेट. लेकर टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। हालांकि सेमीफाइनल में टीम बाहर हो गई, लेकिन अभियांश का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। अभियांश शुरू से ही बेहद मेहनती क्रिकेटर माने जाते हैं। कोच और परिजनों का मानना है कि आने वाले वर्षों में वे और ऊंचाइयों को छूएंगे। दुर्ग जिले के लिए यह गर्व की बात है कि एक स्थानीय खिलाड़ी ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों के सम्मान और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को मजबूत बनाने की अपील

नई दृष्टिबिंदु /रायपुर

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने तथा हथकरघा से निर्मित वस्तुओं के अधिकाधिक उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और लाखों बुनकर परिवारों के सम्मान से जुड़ा जन आंदोलन है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के कुशल बुनकरों द्वारा निर्मित पारंपरिक गमछा धारण कर प्रदेश की समृद्ध हस्तकरघा परंपरा को सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि यह गमछा केवल एक परिधान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान, श्रम, परंपरा और स्थानीय शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है।

हथकरघा उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग का किया आग्रह

अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी और हथकरघा उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि जब हम स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का उपयोग करते हैं, तब हम न केवल उनकी आजीविका को सशक्त बनाते हैं, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह छोटा-सा प्रयास आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में बड़ा योगदान सिद्ध होगा।

मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बुनकर अपनी पारंपरिक कला, उत्कृष्ट शिल्पकौशल और रचनात्मकता के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला रहे हैं। ऐसे प्रतिभाशाली शिल्पकारों का उत्साहवर्धन करना हम सबका सामूहिक दायित्व है।

.राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अभियान से जुड़ने की अपील

अग्रवाल ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर नागरिकों से अपने पसंदीदा हथकरघा उत्पाद के साथ वीडियो अथवा चित्र साझा करने और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अभियान से जुड़ने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस जनभागीदारी से देश-दुनिया तक हमारे बुनकरों की अद्भुत कला, उनकी मेहनत और भारतीय हथकरघा की समृद्ध परंपरा को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासी स्वदेशी अपनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएंगे तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

शिवनाथ नदी में मिला 4 दिन से लापता युवक का शव, पुल पर खड़ी थी साइकिल

बेमेतरा। बेमेतरा थाना क्षेत्र के अमोरा स्थित शिवनाथ नदी. में लगभग 4 दिन से लापता युवक का शव तैरता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान .दुर्गेश पांडेय (लगभग 45 वर्ष)., निवासी ग्राम बिजाभाठ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दुर्गेश पिछले 4 दिनों से लापता था। उसकी साइकिल नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ी मिली थी, जिसके बाद से परिजन और पुलिस उसकी तलाश कर रहे थे।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालु रामलला एवं बाबा विश्वनाथ के दर्शन को रवाना

भारत गौरव ट्रेन से अयोध्या-काशी की यात्रा, नि:शुल्क योजना से साकार हुआ सपना

नई दृष्टिबिंदु / *भिलाई*

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की रामलला दर्शन योजना. के तहत सरगुजा संभाग के .850 श्रद्धालुओं. को लेकर भारत गौरव ट्रेन आज अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन से .अयोध्या धाम. में प्रभु श्री रामलला और .काशी विश्वनाथ धाम. के दर्शन के लिए रवाना हुई।

रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही भक्ति और उल्लास का माहौल रहा। श्रद्धालु ."जय श्रीराम", "हर-हर महादेव". के जयघोष के साथ पहुंचे। पूरा परिसर भक्तिमय नारों से गूंज उठा। अनेक परिवार पारंपरिक वेशभूषा में आए, परिजनों ने तिलक लगाकर और पुष्पवर्षा कर यात्रियों को विदा किया।

भारत गौरव ट्रेन को महापौर .मंजूषा भगत., सभापति .हरविंदर सिंह टिनी., जिला पंचायत अध्यक्ष .नीरूपा सिंह. सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, जिला प्रशासन और आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने श्रद्धालुओं का स्वागत कर यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं को अयोध्या में रामलला के दिव्य दर्शन और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन का सौभाग्य मिलेगा। यात्रा के दौरान आरामदायक रेल यात्रा, स्वच्छ आवास, शुद्ध शाकाहारी भोजन, पेयजल, स्थानीय परिवहन, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोच है कि आर्थिक स्थिति किसी की आस्था में बाधा न बने। इसी भावना से हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क धार्मिक यात्रा का अवसर मिल रहा है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री .राजेश अग्रवाल. ने कहा कि रामलला दर्शन योजना मुख्यमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व की जनकल्याणकारी पहल है। यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को सशक्त बनाने का अभियान है। उन्होंने श्रद्धालुओं से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि की कामना करने और अनुभव साझा करने की अपील की। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं ने भावुक होकर सरकार का आभार जताया। एक बुजुर्ग श्रद्धालु ने कहा कि आर्थिक कारणों से अयोध्या-काशी जाना संभव नहीं था, मुख्यमंत्री की योजना ने वर्षों पुराना सपना पूरा कर दिया।

एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ यात्रा का अवसर मिलेगा, यह कभी नहीं सोचा था। सरकार ने सामान्य परिवारों की भावनाओं का सम्मान किया है।

एक वरिष्ठ श्रद्धालु ने कहा कि भोजन, आवास, सुरक्षा और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था से हम निश्चिंत होकर यात्रा कर रहे हैं। यह योजना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए वरदान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री राजेश अग्रवाल के प्रयासों से संचालित रामलला दर्शन योजना आज प्रदेशवासियों की आस्था को सम्मान देने वाली ऐतिहासिक पहल बन चुकी है। सरगुजा से रवाना हुई भारत गौरव ट्रेन जनसेवा, सुशासन और जनआस्था के समन्वय का प्रेरक उदाहरण है।

आईएएस तनुजा सलामे ने पावरलिफ्टिंग पदक विजेताओं को किया सम्मानित

पावरलिफ्टिंग को राज्य खेल पुरस्कार सूची में शामिल करने पर सकारात्मक विचार का आश्वासन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बुधवार को रायपुर स्थित कार्यालय में आयोजित समारोह में *आईएएस सुश्री तनुजा सलामे, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग. ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पावरलिफ्टिंग खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया।

.कैलाश जैन बरमेचा ने बताया कि. सम्मान समारोह में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाले .जयदीप साहू, प्रियांक मिश्रा एवं अमान शुक्ला. तथा भारतीय टीम के कोच .कृष्णा साहू. उपस्थित रहे।

कैलाश जैन बरमेचा ने बताया कि. इसी क्रम में संभाजीनगर, महाराष्ट्र में आयोजित मास्टर्स राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता .नस्कर टंडन एवं अखिलेश पांडे. तथा छत्तीसगढ़ टीम के कोच .आसिफ अली खान. को भी शॉल-श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। .कैलाश जैन बरमेचा ने बताया कि. कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ पावरलिफ्टिंग संगठन की ओर से संचालक सुश्री तनुजा सलामे को एक मांग-पत्र सौंपा गया। पत्र में अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता छत्तीसगढ़ के पावरलिफ्टिंग खिलाड़ियों को राज्य खेल पुरस्कार, नगद पुरस्कार एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची में स्थान दिया जाए। साथ ही शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए पावरलिफ्टिंग खेल को भी पात्र खेलों की सूची में शामिल किया जाए, ताकि इस खेल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अन्य खेलों के समान अवसर एवं प्रोत्साहन मिल सके।

कैलाश जैन बरमेचा ने बताया कि. मांग-पत्र पर संचालक सुश्री तनुजा सलामे ने आश्वस्त किया कि पावरलिफ्टिंग खेल को संबंधित नियमों में संशोधन कर शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। इससे भविष्य में इस खेल के खिलाड़ियों को भी राज्य शासन द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों एवं सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

कैलाश जैन बरमेचा ने बताया कि. छत्तीसगढ़ पावरलिफ्टिंग संगठन संचालक महोदया के सकारात्मक आश्वासन का स्वागत करता है। संगठन को विश्वास है कि शासन के इस प्रयास से प्रदेश के पावरलिफ्टिंग खिलाड़ियों को नई ऊर्जा एवं प्रोत्साहन मिलेगा तथा वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम और अधिक गौरवान्वित करेंगे।

खास खबर

मुख्य सचिव ने नक्सल मुक्त क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश

कैम्पा मद के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में कैम्पा (उअटढअ) की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित की गई। बैठक में वनों के संरक्षण, पर्यावरण विकास और वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।

***नक्सल मुक्त क्षेत्रों में बढ़ेगी विकास की गति.**

मुख्य सचिव ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कैम्पा मद के तहत वन क्षेत्रों में पुल-पुलियों, पहुंच मार्गों और आवश्यक भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से नक्सल मुक्त हुए क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया, ताकि इन सुदूर क्षेत्रों तक शासन की पहुंच और विकास का लाभ त्वरित गति से पहुंच सके।

.वर्ष 2026-27 के लिए 713.73 करोड़ रुपये की काययीजना अनुमोदित.

बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्ष 2026-27 के लिए 713 करोड़ 73 लाख रुपये की वार्षिक काययीजना को अनुमोदित कर अंतिम स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को भेज दिया गया है, जिसमें से 436 करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा बैठक में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

.पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान.

छत्तीसगढ़ में कैम्पा निधि से किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सिंचित व असिंचित वृक्षारोपण, क्षतिपूर्ति वनीकरण, बांस वनों की पुनर्स्थापना, वनों के घनत्व में वृद्धि के लिए सिल्वीकल्चरल कार्य, वन्यप्राणी प्रबंधन, चरागाह विकास, चेक डैम व तालाबों के माध्यम से भू-जल संरक्षण और कनेक्टिविटी सुधार के कार्य निरंतर जारी हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पीसीसीएफ अरूण पाण्डेय, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद, कैंपा सीईओ शालिनी रैना सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और आईआईएम रायपुर के बीच एमओयू

सुशासन, नीति निर्माण और साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रणाली को मिलेगा बढ़ावा

नई दृष्टिबिंदु /रायपुर

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ शासन एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर (क्क्ष्ट फ्रंत्र४१) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (टङ्क्व) पर हस्ताक्षर किए गए।इसका उद्देश्य सुशासन, प्रभावी नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास, साक्ष्य-आधारित निर्णय, अनुसंधान तथा सतत विकास के क्षेत्रों में अकादमिक एवं व्यावसायिक सहयोग को मजबूत करना है।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग की ओर से सचिव भुवनेश यादव एवं आईआईएम रायपुर की ओर से निदेशक-प्रभारी प्रो. संजीव पराशर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, नीति अनुसंधान, परामर्श, डेटा एनालिटिक्स, शोध एवं दस्तावेजीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर जोर

एमओयू के अंतर्गत शासकीय अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास, मिड-कैरियर एग्जीक्यूटिव एवं कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जा सकेंगे। इकोनोमेट्रिक्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक पॉलिसी, नेतृत्व एवं प्रबंधकीय कौशल जैसे क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिए जाएंगे।

नीति अनुसंधान और डेटा आधारित निर्णय को बढ़ावा

दोनों संस्थान नीति अनुसंधान, प्रभाव आकलन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन, बेंचमार्किंग, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, रणनीतिक परामर्श और डेटा आधारित निर्णय सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ की विकास प्राथमिकताओं से जुड़े शोध, केस स्टडी, पॉलिसी ब्रीफ एवं शोध रिपोर्ट भी तैयार की जा सकेंगी।

लाइव एनालिटिक्स प्रोजेक्ट और विद्यार्थियों की सहभागिता

आईआईएम रायपुर के फैकल्टी एवं विद्यार्थियों द्वारा डेटा एनालिटिक्स आधारित लाइव प्रोजेक्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नेंस इनोवेशन एवं एप्लाइड रिसर्च किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों को समर इंटर्नशिप, फील्ड इमर्शन, लाइव कंसल्टिंग, एक्शन रिसर्च एवं कैपस्टोन प्रोजेक्ट के माध्यम से शासकीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा।

ज्ञान एवं विशेषज्ञता का होगा आदान-प्रदान

एमओयू के तहत संयुक्त कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, पॉलिसी डायलॉग, स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन एवं राउंडटेबल आयोजित किए जाएंगे। आईआईएम रायपुर के विशेषज्ञों, शासकीय अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों की प्रशिक्षण, शोध एवं परामर्श गतिविधियों में सहभागिता होगी। लागू नियमों के अधीन अकादमिक संसाधन, शोध प्रकाशन, डेटाबेस, गैर-गोपनीय डेटा एवं तकनीकी विशेषज्ञता भी साझा की जा सकेगी। यह समझौता छत्तीसगढ़ में नीति निर्माण एवं शासन व्यवस्था को अधिक डेटा-आधारित, शोधपरक और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आईआईएम रायपुर की अकादमिक विशेषज्ञता और राज्य नीति आयोग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की नीतिगत समझ के समन्वय से राज्य की विकास प्राथमिकताओं पर अनुसंधान, नवाचार एवं प्रभावी नीति सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है।

भिलाई : सूने मकान का ताला तोड़कर 4.50 लाख के जेवर और नगदी पार

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, पुलिस जांच में जुटी

नई दृष्टिबिंदु /भिलाईनगर

पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना पद्मनाभपुर दुर्ग निवासी प्रॉपर्टी डीलर के घर की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार *प्रदीप मोटवानी. प्रॉपर्टी डीलिंग और फाइनेंस का काम करते हैं। शुक्रवार को परिवार के साथ उपचार के लिए घर में ताला लगाकर गए थे। देर रात वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा का ताला टूटा हुआ है।

घर के अंदर प्रवेश करते ही कमरों का सामान बिखरा पड़ा मिला। अलमारी की तलाशी लेने पर उसमें रखे .1.50 लाख रुपए नगद और लगभग 3 लाख रुपए के सोने के जेवरात. गायब मिले। कुल मिलाकर लगभग .4.50 लाख रुपए. का नुकसान हुआ है।

परिजनों ने आसपास खोजबीन करने के बाद पुलिस को सूचना दी। पीड़ित के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। फुटेज में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा है। पद्मनाभपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है।

भिलाई रिसाली की दो मितानिनों को मिला 'माता यशोदा सम्मान'

विश्व स्तनपान सप्ताह पर रायपुर में हुआ राज्य स्तरीय सम्मान समारोह

नई दृष्टिबिंदु /भिलाई।

विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य संसाधन प्रणाली रळरफ्छ रायपुर के तत्वाधान में रअउळ संस्था द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भिलाई रिसाली क्षेत्र की मितानिनों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

दिनांक 6 अगस्त 2026 को पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में भिलाई रिसाली की मितानिन झामीन साहू और रामेश्वरी निर्मलकर को स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव एवं ठलट के टऊ द्वारा "माता यशोदा सम्मान" से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल शामिल हुए। वरिष्ठ अतिथि के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया और स्वास्थ्य सेवाएं आयुक्त सह संचालक संजीव झा , रअउळ संस्था के सीईओ राजेंद्रन, कायर्कारी संचालक वीनू आनंद, सलाहकार संतोष सही विभाग के सदस्य उपस्थित रहे। जिला दुर्ग से उटड डॉ. मनोज दानी, भिलाई खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. पियाम सिंह, उ्ढट भूमिका वर्मा, जिला समन्वयक श्रीमती अलका दुबे, क्षेत्र समन्वयक पुष्पा मिश्रा, टोमीन साहू, के. एल. कुमारी और मास्टर ट्रेनर दीप्ति साहू भी कार्यक्रम में मौजूद थीं। बताया गया कि प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष ठलट और रळरफ्छ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मां के दूध के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना, शिशुओं के संपूर्ण पोषण और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम में उन 10 माताओं को "यशोदा सम्मान" से सम्मानित किया गया जिन्होंने उन शिशुओं को स्तनपान कराया या मातृ दूध दान किया जिनकी माताओं को दूध की समस्या थी या जिनका निधन हो गया था।

मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया छत्तीसगढ़ का प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड 'कोशल फैब'

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन एवं स्वदेशी प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं माटीकला बोर्ड के विभिन्न हितग्राहियों तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को 10 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक की अनुदान एवं पुरस्कार राशि वितरित की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के नए प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड 'कोशल फैब' का शुभारंभ करते हुए उसके लोगो एवं कैटलॉग का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने हथकरघा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों, विशेषकर बुनकरों एवं शिल्पकारों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस दिवस को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का कोसा, बस्तर की बुनाई तथा प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा उत्पाद देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के हथकरघा उत्पादों को 'लोकल टू ग्लोबल' की नई पहचान दिलाना है। इसके लिए आधुनिक डिजाइन, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, विपणन तथा नए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों एवं शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में 469 आवासविहीन बुनकर परिवारों के लिए बुनकर शेड सह आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी अवधि में आयोजित 47 प्रदर्शनियों के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपये के हथकरघा उत्पादों की बिक्री हुई।

पिछले ढाई वर्षों में 2,001 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई पारिश्रमिक के रूप में 68 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पाँच विक्रय भंडारों तथा केंद्रीय वस्त्रागार के माध्यम से विभिन्न शासकीय विभागों को 93 करोड़ रुपये के वस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त बुनकरों द्वारा निर्मित 436 करोड़ रुपये के वस्त्रों की शासकीय खरीदी की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के पाँच प्रमुख हवाई अड्डों पर छत्तीसगढ़ के हैंडलूम एवं हस्तशिल्प उत्पादों के शोरूम स्थापित किए जा रहे हैं। रायपुर में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल स्थानीय उत्पादों को आधुनिक विपणन मंच उपलब्ध कराएगा। नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्थापित की जा रही है, जिससे 4,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को डिजाइन एवं टेक्सटाइल क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे।

कार्यक्रम का सबसे प्रेरक क्षण बस्तर की आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं का रैंप वॉक रहा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा सिल्क एवं अन्य हैंडलूम परिधानों का प्रदर्शन किया। यह मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ती महिलाओं के आत्मविश्वास और सम्मानजनक पुनर्वास का प्रतीक बना। मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पित महिलाओं से संवाद कर उन्हें शुभकामनाएँ दीं। पर आधारित प्रीमियम ब्रांड 'कोशल फैब' का शुभारंभ किया गया। यह ब्रांड छत्तीसगढ़ के कोसा एवं पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाएगा। एनआईटी के सहयोग से विकसित इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ हुआ। इससे उत्पादों के भंडारण, प्रबंधन और विपणन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। इस अवसर पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत बुनकरों की डायरेक्टरी तथा टाई-डाई एवं बाँधनी रंगाई विषयक पुस्तक का भी विमोचन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 935 छात्र-छात्राओं को 81.83 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। 17 वरिष्ठ बुनकरों को सम्मान राशि दी गई। हथकरघा संचालनालय के माध्यम से 49 बुनकरों के लिए बुनकर शेड सह आवास निर्माण हेतु 1.22 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई। पाँच बुनकर सहकारी समितियों को भवन निर्माण के लिए 75 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई तथा 85 बुनकरों को उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए। हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा 30 शिल्पकारों को आधुनिक टूल किट तथा माटीकला बोर्ड द्वारा 70 पंजीकृत माटी शिल्पियों को विद्युत चाक प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने तथा 'सेल्फी विद स्वदेशी' अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीद न केवल बुनकरों, शिल्पकारों और कारीगरों की आजीविका को सशक्त बनाती है।

संपादकीय

सूदखोरी ने किसानों का निकाला दम..

राजीव चौबे
फाउंडर राष्ट्रीय चेतना न्यूज

50 से 70 तक के दशकों की अधिकतर हिंदी फिल्मों के ग्रामीण परिवेश में मुख्य खलनायक गाँव का सूदखोर महाजन होता था और ये फिल्मी कहानी मात्र नहीं थी सचमुच ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोरी के दम पर ही न जाने कितने लोग सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक बन गए और न जाने कितने छोटे किसान भूमिहीन हो गए ! यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो सन 2000 में नया राज्य बनने के बाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सहकारी समितियों से किसानों को जो ऋण सुविधाएं सुलभ हुई उसके बाद ग्रामीण अंचल में व्यवस्थाएं काफी बदली , किसान संपन्न हुए और सूदखोरी के चंगुल से मुक्त भी हुए लेकिन समाज से सूदखोरी का अभिशाप खत्म नहीं हुआ सूदखोरी की ये ग्रामीण व्यवस्था अब गावों से निकल कर शहरों में अपने पैर प्रसार चुकी है । आज से लगभग एक साल पहले रायपुर पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कारवाई कर रायपुर के कुख्यात सूदखोर तोमर बंधुओं को घेरे में लिया था , ये सचमुच बड़े आश्चर्य का विषय है कि कुछ वर्ष पहले अंडे का ठेला लगाने वाले दोनों भाई करोड़ों में खेल रहे थे । वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के बाद कुछ नाटकीय घनाएं भी हुई करनी सेना के कथित अध्यक्ष ने पूरे क्षत्रिय समाज को गृह मंत्री विजय शर्मा और रायपुर पुलिस के विरुद्ध उकसाने का प्रयास किया और बुरी तरह से असफल हो कर लौट भी गए। दूसरी ओर उस घटना के बाद भी तोमर बंधुओं के गुर्गों का आतंक कम नहीं हुआ था । उनकी फरारी के दौरान ही एक महिला यूट्यूबर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी । दैनिक समाचार पात्र पत्रिका के पोर्टल में दिनांक 17 -06 - 2025 की खबर के अनुसार पीड़िता ने इसकी शिकायत डीडी नगर थाने में की थी । पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में भी लिया था । वास्तविक में रायपुर पुलिस की कायर्वाही सूदखोरी के अवैध कारोबार का एक प्रतिशत हिस्से पर भी नहीं हुई थी , आज की तारीख में रायपुर , दुर्ग , भिलाई में ही सूदखोरी का अवैध कारोबार सैकड़ों करोड़ रु प्रतिमाह का है। पिछले साल रायपुर में तोमर बंधुओं के खिलाफ हुई कारवाई से कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि प्रदेश की सरकार इन सूदखोरों के पंजे में फंसे जरूरतमंद लाचार और गरीब जनता के प्रति संवेदनशील हो गई है इसीलिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इस सूदखोरी के अवैध कारोबार के विरुद्ध मुहीम छेड़ दी गई है और अब पूरे प्रदेश में इन सुखी लालाओं के विरुद्ध कारवाइयां होंगी लेकिन बाद में समझ आया की तोमर बंधुओं के विरुद्ध पुलिस की कारवाई का सूदखोरी के अवैध व्यापार से कोई लेना देना ही नहीं था। सूदखोरों के चंगुल में फंसे मजलूमों से छत्तीसगढ़ सरकार का कोई वास्ता ही नहीं था वो तो बस गलती से तोमर बंधू और सत्ताधारी दल के किसी बहुत बड़े नेता के करीबी मित्र के बीच जमीन कब्जे का विवाद उत्पन्न हुआ और तोमर बंधुओं की रंगदारी बड़े नेता जी को खटक गई और बस नेता जी के प्रेस्टीज के लिए वो कारवाई हुई उसके बाद से अब तक पूरे प्रदेश में किसी भी शहर में किसी भी सूदखोर के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई है। दरअसल ये सूदखोर पूरे देश में एक सामानांतर अर्थ व्यवस्था चला रहे हैं जिससे काला धन तूफानी गति से बढ़ रहा है आप समझने की कोशिश करें ब्याज पर चलने वाला पैसा नगद यानि की अनएकॉउंटेड पैसा होता है जो निश्चित रूप से काला धन है और इन सूदखोरों की ब्याज दरें भी ऐसी होती हैं कि आम आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता । क्या आप सोच सकते हैं कि ये सूदखोर 5 % महीने से ले कर 11 % प्रतिमाह तक की ब्याज दर पर पैसा चला कर गरीब व्यापारियों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं वसूली के लिए गुंडे भी पाल रहें और शहर में अपराध को बढ़ावा भी दे रहे हैं। भिलाई शहर में सूदखोरों का बड़ा नेटवर्क सक्रीय है इस कारोबार में व्यापारी , नेता , बी एस पी कमर्चारी , सहकारी साख समितियों के पदाधिकारी और कमर्चारी और अन्य कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं । ये सूदखोर सामान्यत : 5 % मासिक से लेकर 11 % मासिक की ब्याज दर पर ऋण देते हैं फल और सब्जी के फुटकर व्यापारी जिन्हे खरीदी के लिए प्रतिदिन पैसों की आवश्यकता होती है ऐसे व्यापारी 11 % प्रतिमाह की ब्याज दर पर क़र्ज लेते हैं। भिलाई के खुदरा फल और सब्जी व्यापारी बताते हैं जब ये तीन महीने के लिए दस हजार रु लेते हैं तो इन्हे तीन महीनों में बारह हजार रू लौटने होते हैं लेकिन सूदखोर इन्हे पहले महीने का ब्याज एक हजार रु काट कर सिर्फ नौ हजार रु देता है अब उस सूदखोर की लागत होती है नौ हजार और उसपर ब्याज मिलता है तीन हजार जो हुआ तीन महीने का 33 % अर्थात 11 % प्रतिमाह अब आप ही सोचिये जहाँ बैंकों में आपका पैसा 10 साल में दोगुना होता है वहां इन सूदखोरी के धंधे में पैसा नौ महीनों में ही दोगुना हो जा रहा है। लोन देने के सख्त प्रावधानों और जटिल प्रक्रियाओं के बाद भी बैंक में प्रतिवर्ष हजारों खाते एन पी ए हो रहे हैं बैंक के करोड़ों रु डूब रहे हैं लेकिन सिर्फ आधार कार्ड रख कर बिना किसी लिखा पढ़ी के बड़ी ही सरलता से उपलब्ध इन सूदखोरों का पैसा बहुत कम डूबता है क्योंकि ये हर हाल में अपना पैसा वसूलना जानते हैं , एक तो सूदखोरी के धंधे में संलिप्त अधिकतर लोग रसूखदार और बाहुबली किस्म के हैं इसके अलावा वसूली के लिए ये लोग गुंडे बदमाशों का उपयोग भी करते हैं इस धंधे में जहाँ देखते ही देखते ब्याज की रकम मूलधन से कई गुना अधिक हो जाती है और इसकी वसूली के लिए ये सूदखोर खुले आम गुंडागर्दी करते हैं लाचार और निरीह कजर्दार के पास कोई सहारा नहीं होता पुलिस के पास जाने पर इसे पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध बता कर प्रार्थी को कोर्ट जाने की सलाह दी जाती है , कोर्ट में देर सबेर न्याय तो मिल सकता है लेकिन गरीब को सूदखोरों के गुंडों या गुंडागर्दी से सुरक्षा नहीं मिल सकती अत : वो क़र्ज चुकाने के लिए अपना सब कुछ बेचने तक को मजबूर होता है । बैंकों के पहाड़ जैसे नियमों से त्रस्त छोटे छोटे व्यापारियों या प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों की पैसों की आवश्यकता और मजबूरी ही इस पूरे गोरख घंधे का मूल आधार है इसलिए पुलिस इस बड़े समुन्दर से तोमर बंधू जैसी एक्का दुक्का मछलियों को पकड़ती रहेगी लेकिन इस कारोबार को तब तक खत्म नहीं कर सकती जब तक शहरी बैंकों में भी लोन की प्रक्रिया सरल नहीं हो जाती।

सूचनाओं के संजाल और भरोसे का संकट !

संजय उवाच
प्रो. संजय द्विवेदी

सोशल मीडिया ने बदल दी है जनसंचार की दुनिया

भारतीय समाज में किसी नए प्रयोग को लेकर इतनी स्वीकायर्ता कभी नहीं थी, जितनी कम समय में सोशल मीडिया ने अर्जित की है। जब इसे सोशल मीडिया कहा गया तो कई विद्वानों ने पूछा च्अरे भाई क्या बाकी मीडिया अनसोशल है? अगर वे भी सामाजिक हैं, तो यह सामाजिक मीडिया कैसे?ज्ज किंतु समय ने साबित किया कि यह वास्तव में सोशल मीडिया है। अब उससे आगे डीफफेक ने सारा कुछ बदलकर रख दिया है। जनरेटिव एआईऔर डीपफेक टूल्स की मदद से अब किसी भी व्यक्ति का फर्जी वीडियो या ऑडियो बनाना बेहद आसान और सस्ता हो गया है।कुछ ही सेकंड के ऑडियो या वीडियो सैंपल से तैयार यह तकनीक आम आदमी से लेकर दिग्गजों तक की पहचान के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है।

सृजनात्मकता का विस्फोट-

पारंपरिक मीडिया की बंधी-बंधाई और एकरस शैली से अलग हटकर जब भारतीय नागरिक इस पर विचरण करने लगे तो लगा कि रचनात्मकता और सृजनात्मकता का यहां विस्फोट हो रहा है। दृश्य, विचार, कमेंट् और निजी सृजनात्मकता के अनुभव जब यहां तैरने शुरू हुए तो लोकतंत्र के पहरूओं और सरकारों का भी इसका अहसास हुआ। आज वे सब भी अपनी सामाजिकता के विस्तार के लिए सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं भी कहा कि च्सोशल मीडिया नहीं होता तो हिंदुस्तान की क्रियेटिविटी का पता ही नहीं चलता।ज्ज सोशल मीडिया अपने स्वभाव में ही बेहद लोकतांत्रिक है। जाति, धर्म, भाषा, लिंग और रंग की सीमाएं तोड़कर इसने न सिर्फ पारंपरिक मीडिया को चुनौती दी है वरन यह सही मायने में आम आदमी का माध्यम बन गया है। इसने संवाद को निंरतर, समय से पार और लगातार बना दिया है। इसने न सिर्फ आपकी निजता को स्थापित किया है वरन एकांत को भी भर दिया है।

निजता अब सामूहिक संवाद में बदल रही-

सूचनाएं आज मुक्त हैं और वे इंटरनेट के पंखों पर उड़ रही हैं। सूचना २१ वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत बनी तो सोशल मीडिया, सभी उपलब्ध मीडिया माध्यमों में सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गया। सूचनाएं अब ताकतवर देशों, बड़ी कंपनियों और धनपतियों द्वारा चलाए जा रहे प्रचार माध्यमों की मोहताज नहीं रहीं। वे कभी भी वायरल हो सकती हैं और कहीं से भी वैश्विक हो सकती हैं। स्नोडेन और जूलियन असांजे को याद कीजिए। सूचनाओं ने अपना अलग गणतंत्र रच लिया है। निजता अब सामूहिक संवाद में बदल रही है। वार्तालाप अब वैश्विक हो रहे हैं। इस आभासी दुनिया में आपका होना ही आपको पहचान दिला रहा है। च्ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होयज्ज कहने वाले देश में अब एक वाक्य का विचार क्रांति बन रहा है। यही विचार की ताकत है कि वह किताबों और विद्वानों के इंतजार में नहीं है।

सोशल साइट्स का समाजशास्त्र अलग है। यहां ट्वीट फैशन भी है और सामाजिक काम भी। फेसबुक और ट्विटर नए गणराज्य हैं। निजी जिंदगी से लेकर जनांदोलन और चुनावों तक अपनी गंभीर मौजूदगी को दर्ज करवा रहा ये माध्यम, सबको आवाज और सबकी वाणी देने के संकल्प से लबरेज है। कंप्यूटर से आगे अब स्मार्ट होते मोबाइल इसे गति दे रहे हैं। यहां मोती भी हैं और कीचड़ भी- अपने तमाम नकारात्मक प्रभावों के बावजूद इसके उपयोग के प्रति बढ़ती ललक बताती है कि सोशल मीडिया का यह असर अभी और बढ़ने वाला है। यह मान लेने में हिचक नहीं करनी चाहिए कि यहां मोती भी हैं और कीचड़ भी। झूठ, बेईमानी, अपराध और बेवफाई के किस्से हैं तो दूसरी तरफ निभ रही दोस्तियों की लंबी कहानियां हैं। हो चुकी और चल रही शादियों की लंबी श्रृंखला है। कभी किसी भी माध्यम के प्रति इतना स्वागत भाव नहीं था। फिल्में आई तो अच्छे घरों के लोग न इसमें काम करते थे, ना ही वे फिल्में देखने जाते थे। मां-पिता से छिपकर युवा सिनेमा देखने जाते थे। टीवी आया तो उसे भी इडियट बाक्स कहा गया। टीवी को लगातार देखते हुए भी हिंदुस्तान उसके प्रति आलोचना के भाव से भरा रहा और आज भी है। किंतु सोशल मीडिया के प्रति आरंभ से ही स्वागत भाव है। इसके प्रति समाज में अस्वीकृति नहीं दिखती क्योंकि यह कहीं न कहीं संबंधों का विस्तार कर रहा है। संवाद की गुंजाइश बना रहा है। रहिए कनेक्ट के नारे को साकार कर रहा है। इसके सही और सार्थक इस्तेमाल से छवियां गढ़ी जा रही हैं, चुनाव लड़े और जीते जा रहे हैं।

इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा किसी भी माध्यम का गलत इस्तेमाल हमें संकट में ही डालता है। यह समय इंफारमेशन वारफेयर का भी है और साइको वारफेयर का भी। इस दौर में सूचनाएं मुक्त हैं और प्रभावित कर रही हैं। यहां संपादक अनुपस्थित है और रिपीटर भी प्रामाणिक नहीं हैं। इसलिए सूचनाओं की वास्तविकता भी जांची जानी चाहिए। कई बार जो संकट खड़े हो रहे हैं, वह वास्तविकता से दूर होते हैं। सोशल मीडिया की पहुंच और प्रभाव को देखते हुए यहां दी जा रही सूचनाओं के सावधान इस्तेमाल की जरूरत भी महसूस की जाती है। इसे अफवाहें, तनाव और वैमनस्य फैलाने का माध्यम बनाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। चुनावों या संवेदनशील राजनीतिक मौकों पर राजनेताओं के फर्जी भाषणों या बयानों वाले डीपफेक वीडियो का प्रसार मतदाताओं को भ्रमित कर सकता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्षता और जनमत को गलत दिशा में मोड़ने का एक खतरनाक हथियार बनता जा रहा है।वॉयस क्लोनिंग (आवाज की नकल) और वीडियो डीपफेक का उपयोग करके अब कॉरपोरेट घरानों, बैंकों और आम नागरिकों को चूना लगाने के मामले तेजी से बढ़े हैं।ठग फेक आइडेंटिटी के जरिए बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं।हालांकि डीपफेक और भ्रामक कृत्रिम सामग्री (स्त्रङ्क) पर लगाम कसने के लिए अब कानूनों को सख्त किया गया है। इसके तहत एआई-जनित फोटो, वीडियो या ऑडियो पर स्पष्ट 'डिजिटल स्टैम्प' या लेबल लगाना अनिवार्य किया गया है ताकि उपयोगकर्ता पहली नजर में पहचान सकें।

शक्ति का हो सार्थक इस्तेमाल-

सोशल मीडिया में समरस और मानवीय समाज की रचना की शक्ति छिपी है। किंतु उसकी यह संभावना उसके इस्तेमाल करने वालों में छिपी हुयी है। इसका सही इस्तेमाल ही हमें इसके वास्तविक लाभ दिला सकता है।सामाजिक सवालों पर जागरूकता और जनचेतना के जागरण में भी यह माध्यम सहायक सिद्ध हो सकता है। आम चुनावों में राजनीतिक दलों ने इस माध्यम की ताकत को इस्तेमाल किया और समझा है। आज युवा शक्ति के इस माध्यम में बड़ी उपस्थित के चलते इसे सामाजिक बदलाव और परिवर्तन का वाहक भी माना जा रहा है। सकात्मकता से भरे-पूरे युवा और सामाजिक सोच से लैस लोग इस माध्यम से उपजी शक्ति को भारत के निर्माण में लगा सकते हैं। ऐसे समय में जब सोशल मीडिया की शक्ति का प्रगटीकरण साफ है, हमें इसके सावधान, सतर्क और समाज के लिए उपयोगी प्रयोगों की तरफ बढ़ने की जरूरत है। यदि ऐसा संभव हो सका तो सोशल मीडिया की शक्ति हमारे लोकतंत्र के लिए वरदान साबित हो सकती है।डीपफेक का सबसे बुरा शिकार अक्सर महिलाएं और प्रसिद्ध हस्तियां हो रही हैं, जिनकी तस्वीरें या वीडियो का गलत इस्तेमाल करके उनकी मानहानि या ऑनलाइन उत्पीड़न किया जाता है।यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा पर सीधा हमला है।

एंगेजमेंट की भूख से बढ़ता खतरा-

सोशल मीडिया के एल्गोरिदम 'एंगेजमेंट' (व्यूज और लाइक्स) के भूखे होते हैं। झूठी और सनसनीखेज खबरें सच की तुलना में तेजी से फैलती हैं, जिससे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का कारोबार फल-फूल रहा है।यह केवल सरकारों या टेक कंपनियों की लड़ाई नहीं है। मुख्यधारा के मीडिया और जागरूक नागरिकों को आगे आकर फेक नैरेटिव्स का खंडन करना होगा और तकनीक के सकारात्मक इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए एक सुरक्षित डिजिटल स्पेस का निर्माण करना होगा।पारंपरिक कहावत "आंखों देखी पर विश्वास करो" अब डिजिटल युग में दम तोड़ रही है। जब वीडियो और तस्वीरों पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है, तो समाज में हर प्रामाणिक और सच्ची घटना पर भी शक का माहौल पैदा होने लगता है।सोशल मीडिया ने अपनी लोकप्रियता के साथ भरोसे का संकट भी खड़ा किया है, इसमें दो राय नहीं है।

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं।)

ढाई साल की उपलब्धियाँ- छत्तीसगढ़ का श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान

पिछले ढाई साल में श्रम विभाग ने गढ़ी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की मिसाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक ऐतिहासिक पहल की हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सुशासन, पारदशिर्ता और तकनीकी नवाचार से जोड़ते हुए श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। वहीं श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में विभाग ने श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ तेजी और सरलता से पहुंचाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं।

श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में हो रहा है सुधार.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। श्रमिकों के पंजीयन, सहायता और योजनाओं के लाभ को अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाने के लिए श्रम विभाग ने नई यूजर-फ्रेंडली वेबसाइट ँ३३स्र://२ँ१ें५ं८३ी ़ॅङ्म५.्रल्ल और श्रमेव जयते मोबाइल एप विकसित किया है, जिससे श्रमिक अब ऑनलाइन आवेदन, पंजीयन और अन्य सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर रहे हैं।

.रोजगार सृजन के साथ श्रमिक अधिकार भी हो रहा है मजबूत.

ढाई वर्षों में श्रम विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया है। 5 नए जिलों (मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं सक्ती) में श्रम अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु 20 पदों का सृजन किया गया है। वतर्मान में 10 जिलों के सहायक श्रमायुक्त कार्यालय तथा 23 जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय संचालित है। इस प्रकार राज्य के सभी 33 जिलों में श्रम कार्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न पदों पर नियुक्तियां कर विभागीय क्षमता को भी बढ़ाया गया है।

उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। दुकानों एवं स्थापना अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, महिला श्रमिकों के लिए रात्रिकालीन कार्य की सुविधा, फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने जैसे अनेक निणर्यों ने रोजगार सृजन के साथ श्रमिक अधिकारों को भी मजबूत किया है।

.लगभग 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित.

श्रम विभाग की उपलब्धियों में सबसे उल्लेखनीय सफलता श्रमिक पंजीयन और हितलाभ वितरण रही है। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2026 के बीच लगभग 12.65 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया। लगभग 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया, जिन पर लगभग 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई। निर्माण श्रमिकों को लगभग 780 करोड़ रुपये तथा असंगठित श्रमिकों को लगभग 187 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। लाभ वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (उ्रइळ) प्रणाली लागू की गई है।

.मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 24 घंटे, सात दिन संचालित.

मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्रों की स्थापना श्रमिकों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र 24 घंटे, सात दिन संचालित किया जा रहा है। राज्यभर में मोबाइल शिविर आयोजित कर लाखों श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण और आवेदन संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के श्रमिकों को भी सरकारी सेवाओं का लाभ घर के समीप मिल रहा है। राज्य सरकार ने श्रमिक परिवारों के सामाजिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत किया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत आवास सहायता राशि बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई है। मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, छात्रवृत्ति, श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिला है।

.1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता.

महिला श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र की 1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता प्रदान की गई। वहीं 'शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना' के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेधावी शिक्षा सहायता, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग तथा छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। हजारों विद्यार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे श्रमिक परिवारों के सपनों को नई उड़ान मिल रही है।

.छत्तीसगढ़ का श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिक कल्याण को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का जो संकल्प लिया गया है, उसे श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में श्रम विभाग प्रभावी रूप से जमीन पर उतार रहा है। पारदर्शी व्यवस्था, तकनीकी नवाचार, त्वरित सेवा, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक सम्मान की भावना ने छत्तीसगढ़ को श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान दी है।

ढाई वर्षों की यह यात्रा केवल योजनाओं और आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि लाखों श्रमिक परिवारों के जीवन में आए विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि की नई शुरुआत है।

भीष्म साहनी

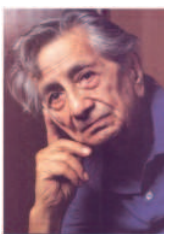

हिन्दी साहित्य के आधुनिक परिदृश्य में भीष्म साहनी का नाम उन रचनाकारों में लिया जाता है जिन्होंने साहित्य को जनमानस से जोड़ा। वे प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी लेखक माने जाते हैं और अपने लेखन के माध्यम से समाज के यथार्थ, संघर्ष तथा मानवीय मूल्यों को उजागर करते रहे।

भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ। उनके पिता हरबंस लाल साहनी समाजसेवी थे और बड़े भाई बलराज साहनी हिन्दी फि ल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता बने। उन्होंने लाहौर के गवनर्मेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. तथा पंजाब विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की।

साहनी जी ने व्यापार, अध्यापन और पत्रकारिता से जीवन की शुरुआत की। वे ह्यइप्टाह्ल रंगमंच से जुड़े और मास्को में अनुवादक के रूप में कार्य करते हुए रूसी साहित्य को हिन्दी में प्रस्तुत किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने स्थायी अध्यापन किया।

भीष्म साहनी का साहित्य यथाथर्वादी और जनवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। वे माक्सर्वादी विचारधारा से प्रभावित थे, परन्तु मानवीय मूल्यों को सदैव प्राथमिकता देते रहे। उनकी रचनाओं में मध्यवर्गीय विसंगतियाँ, निम्नवर्गीय संघर्ष, राजनीति का भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और जातिवाद का चित्रण मिलता है। वे नारी शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व विकास के समर्थक थे।

साहनी जी धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे। उनके साहित्य में शोषणविहीन, समतामूलक समाज की स्थापना की आकांक्षा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे लोकगीतों और लोकजीवन के मर्मज्ञ थे तथा रंगमंच से भी गहरा लगाव रखते थे।

उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें लोटस पुरस्कार (1970), साहित्य अकादमी पुरस्कार (1975), शिरोमणि लेखक सम्मान (1975), सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार (1983) और पद्म भूषण (1998) से सम्मानित किया गया।

लेखन की सच्चाई ही जीवन की सच्चाई है।

भीष्म साहनी का साहित्य जीवन और समाज का यथार्थ चित्रण है। उन्होंने जिस जीवन को जिया, उसी का यथावत चित्र अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। उनके लिए लेखन और जीवन धर्म में कोई भेद नहीं था। यही कारण है कि वे हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और उससे भी आगे निकलने वाले रचनाकार माने जाते हैं।

लेखिका
वंदना चौधरी

जामुल पुलिस ने बंद फैक्ट्री से लोहा चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

40,000 की चोरी गई लोहे की प्लेट बरामद, न्यायालय में पेश

नई दृष्टिबिंदु /दुर्ग।

दुर्ग पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में संपत्ति संबंधी अपराधों पर कार्रवाई करते हुए .थाना जामुल. क्षेत्र में बंद फैक्ट्री से लोहा चोरी करने वाले .2 आरोपियों को गिरफ्तार. और .1 विधि से संघर्षरत बालक. के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है। आरोपियों के कब्जे से लगभग . ?40,000 मूल्य की लोहे की प्लेट. भी बरामद की गई है।

.क्या है पूरा मामला.

थाना जामुल क्षेत्रांतर्गत .बी.एस. कास्टिंग कंपनी, प्लॉट नंबर 34-बी, इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई. से रात्रि के समय लोहे की प्लेट चोरी होने की रिपोर्ट पर प्रार्थी जितेन्द्र पाण्डेय, निवासी जवाहर नगर भिलाई की शिकायत पर अपराध क्रमांक .549/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस. के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

प्रार्थी ने बताया कि दिनांक 31.07.2026 की रात फैक्ट्री से लगभग ?40,000 की लोहे की प्लेट अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर ली गई।

.सीसीटीवी और मुखबिर सूचना से हुआ खुलासा.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण और फैक्ट्री में लगे .सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण. किया। मुखबिर सूचना और फुटेज में दिखे संदिग्धों के हुलिये के आधार पर .रवि विश्वकर्मा उर्फ खेलू. को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पूछताछ में रवि ने अपने साथी .राहुल कुर्रे. और एक विधि से संघर्षरत बालक के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गई लोहे की प्लेट बरामद कर जप्त की गई।

.इस तरह देते थे चोरी को अंजाम.

पुलिस के अनुसार आरोपी रात्रि के समय बंद पड़ी फैक्ट्री में प्रवेश कर भारी लोहे की प्लेट चोरी कर ले जाते थे। सुनसान समय का फायदा उठाकर वे पकड़े जाने से बचने की कोशिश करते थे। आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने यह वारदात की थी।

.गिरफ्तार आरोपी.

1. .रवि विश्वकर्मा उर्फ खेलू., उम्र 21 वर्ष, निवासी गौतम नगर, सन्यासी गली, थाना खुर्सीपार, दुर्ग

2. .राहुल कुर्रे., उम्र 21 वर्ष, निवासी गौतम नगर, सेक्टर-1, जोन-1, थाना खुर्सीपार, भिलाई, दुर्ग

3. .एक विधि से संघर्षरत बालक.

दिनांक 07.08.2026 को दोनों वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध .किशोर न्याय अधिनियम. के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई।

.दुर्ग पुलिस की अपील.

दुर्ग पुलिस ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों से अपील की है कि अपने परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या .डायल-112. पर दें। संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खास खबर

चिरायु योजना बनी बच्चों के लिए जीवनदायिनी

नई दृष्टिबिंदु /बेमेतरा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम "चिरायु योजना" * बेमेतरा जिले में जन्मजात विकृतियों से पीड़ित बच्चों के लिए संजीवनी बनकर सामने आई है। योजना के तहत जन्मजात हृदय रोग और कटे-फटे होंठ-तालु से ग्रसित तीन बच्चों का निःशुल्क सफल उपचार कर उन्हें स्वस्थ जीवन दिया गया। यह उपचार .चिरायु योजना एवं आयुष्मान भारत योजना. के समन्वय से संभव हुआ।

जन्मजात विकृतियों से पीड़ित 3 बच्चों का नि :शुल्क सफल उपचार, मिली नई जिंदगी

कलेक्टर .सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई. के निर्देश और सीएमएचओ .डॉ. अमृतलाल रोहलेडर. के मार्गदर्शन में बीएमओ .डॉ. शरद कोहाड़े., डीपीएम .सुश्री लता बंजारे. एवं सहायक जिला नोडल अधिकारी .डॉ. ऋषभ शर्मा. के समन्वित प्रयासों से जिले में यह उपलब्धि हासिल हुई।

.1. प्रेरणा साहू का हृदय ऑपरेशन सफल.

ग्राम झिरिया, विकासखंड बेमेतरा निवासी .कु. प्रेरणा साहू., पिता परमानंद साहू, जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित थीं। 23 मई 2026 को आंगनबाड़ी केंद्र झिरिया में चिरायु दल ने जांच के दौरान बच्ची के दिल में मर्मर साउंड पहचाना। ईको जांच में हृदय में छेद की पुष्टि हुई। 20 जुलाई 2026 को उच्च चिकित्सा संस्थान में भर्ती कर 28 जुलाई 2026 को सफल ऑपरेशन किया गया। अब प्रेरणा पूरी तरह स्वस्थ है।

. रिशिका पाल का हुआ निःशुल्क हृदय उपचार.

बेमेतरा नगर वार्ड क्रमांक-09 निवासी .कु. रिशिका पाल., पिता बंशी पाल, गंभीर हृदय रोग से ग्रसित थीं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को चिरायु योजना के तहत निःशुल्क इलाज का भरोसा दिलाकर रेफर किया गया। 20 मई 2026 को भर्ती कर 22 मई 2026 को सफल हृदय ऑपरेशन हुआ। उपचार के बाद रिशिका अब सामान्य जीवन जी रही है।

तरणी चंद्राकर की लौटी मुस्कान.

ग्राम कोदवा निवासी .कु. तरणी चंद्राकर., पिता सोनलाल चंद्राकर, जन्मजात कटे-फटे होंठ-तालु से पीड़ित थीं। चिरायु दल ने चिन्हांकन कर उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर किया। 11 जुलाई 2026 को कटे-फटे होंठ का निःशुल्क सफल ऑपरेशन हुआ। उपचार के बाद बच्ची के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है।

.समय पर पहचान और निःशुल्क उपचार.

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि चिरायु योजना के तहत बच्चों की समय पर पहचान, विशेषज्ञ जांच, रेफरल और निःशुल्क उपचार की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। इस कार्य में चिरायु दल के .डॉ. अभिषेक यादव, डॉ. दिलीप चंद्रवंशी, डॉ. प्रीति ठाकुर, डॉ. ज्योति वर्मा, हिना सिन्हा, खिलेन्द्र साहू. सहित अन्य सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही। विभाग ने कहा कि आगे भी ऐसे बच्चों का सतत चिन्हांकन कर .चिरायु और आयुष्मान भारत योजना. के माध्यम से निःशुल्क उपचार का लाभ दिलाया जाएगा।

प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने CMHO को हटाकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की

प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ, छत्तीसगढ़ ने सौंपा ज्ञापन

नई दृष्टिबिंदु /बेमेतरा

प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ, छत्तीसगढ़. ने जिला बेमेतरा में पदस्थ .मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (उटलड). के विरुद्ध मुख्यमंत्री, कलेक्टर, अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को विस्तृत शिकायत ज्ञापन सौंपकर .उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच. और .उटलड को तत्काल हटाने. की मांग की है।

संघ का कहना है कि बेमेतरा में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को लंबे समय से .मानसिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रताड़ना. का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में आरोप है किः - CHO संवर्ग के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार किया जाता है।

- समीक्षा बैठकों में अभद्र भाषा का प्रयोग होता है।

- केवल CHO को लक्ष्य बनाकर ठलट के ळडफके विपरीत अन्य संवर्गों के कार्य भी कराए जाते हैं। - उच्च अधिकारियों के समक्ष उलड की कायशैली को लेकर नकारात्मक एवं भ्रामक प्रस्तुतीकरण किया जाता है। संघ ने महिला उलड के साथ .गरिमा-विरोधी व्यवहार. का भी आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार समीक्षा बैठकों के दौरानः - कुछ महिला कमर्चारियों के कपड़े पकड़कर उन्हें खींचने, लेजर लाइट से शरीर विशेषकर वक्ष क्षेत्र की ओर संकेत करने,

- सार्वजनिक रूप से हंसी-मजाक करने

जैसी घटनाएं हुईं।

- एक महिला कमर्चारी से कथित रूप से ह्र.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या?.ह्व जैसी व्यक्तिगत एवं अपमानजनक टिप्पणी की गई। संघ ने इन शिकायतों की जांच .कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (ढडरल्ल अू३). और सुप्रीम कोर्ट के .श्रॅं बनाम राजस्थान राज्य (1997). के निर्देशों के अनुसार कराने की मांग की है। आरोप सिद्ध होने पर कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग भी की गई है।

.स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा असर.

संघ के अनुसार जिन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में केवल एक उलड पदस्थ है, उन्हें सप्ताह में सेक्टर बैठक, फील्ड भ्रमण, हेल्थ मेला और अन्य अभियानों के लिए केंद्र बंद कर जाना पड़ता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में .ओपीडी, दवा वितरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं. प्रभावित हो रही हैं। 7 दिन में कारर्वाई की मांग, अन्यथा आंदोलन.

संघ ने संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21, ठलट उलड ळडफऔर ढडरल्ल अू३ का हवाला देते हुए कहा है कि जांच की निष्पक्षता के लिए .उटलड बेमेतरा को जांच अवधि तक पद से हटाया. जाए। संघ ने शासन से .7 दिन के भीतर प्रभावी कारर्वाई. शुरू करने का आग्रह किया है। चेतावनी दी है कि यदि कारर्वाई नहीं हुई तो संघ विधिसम्मत एवं शांतिपूर्ण तरीके से .चरणबद्ध आंदोलन. करेगा।

एक महीने से कमिश्नर विहीन दुर्ग नगर निगम ;सरकार तुरंत करे नियुक्ति – अरुण वोरा

नई दृष्टिबिंदु /दुर्ग।

दुर्ग नगर निगम में पिछले लगभग एक महीने से आयुक्त (कमिश्नर) का पद रिक्त होना राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता और दुर्ग शहर के प्रति उसकी गंभीर उदासीनता को उजागर करता है। जिस नगर निगम पर लाखों नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और शहर के विकास की जिम्मेदारी है, वहां इतने लंबे समय तक पूणर्कालिक कमिश्नर की नियुक्ति नहीं होना सरकार की कायर्शैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

दुर्ग शहर के पूर्व विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने कहा कि आज दुर्ग की जनता सफाई, पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट सहित बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। दूसरी ओर, नगर निगम में पूणर्कालिक कमिश्नर नहीं होने से प्रशासनिक फैसले लंबित हैं और विकास कार्यों की रफ्तार थम गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार बताए कि एक महीने से दुर्ग नगर निगम को पूणर्कालिक कमिश्नर क्यों नहीं मिल पाया? क्या दुर्ग की जनता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है?

अरुण वोरा ने कहा कि भाजपा सरकार के पास घोषणाएं करने का समय है, लेकिन शहरों की व्यवस्था संभालने का समय नहीं है। यदि सरकार अधिकारियों की नियुक्ति तक समय पर नहीं कर पा रही है, तो सुशासन के उसके सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक पद को इतने लंबे समय तक रिक्त रखना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर दुर्ग नगर निगम में पूणर्कालिक कमिश्नर की नियुक्ति करने की मांग करते हुए कहा कि दुर्ग की जनता को सरकार की प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता की कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शहर का विकास और नागरिक सुविधाएं किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार इस जिम्मेदारी से लगातार मुंह मोड़ रही है।

अरुण वोरा ने कहा कि दुर्ग जैसे प्रदेश के प्रमुख शहर की नगर निगम को भगवान भरोसे छोड़ देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

बेमेतरा में खाद्य कारोबारियों की जागरूकता बैठक आयोजित की गई

एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु /बेमेतरा।

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संरक्षण और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से *छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एनालॉग पनीर पर लगाए गए एक वर्षीय प्रतिबंध. के संबंध में बुधवार को जिला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा होटल व्यवसायियों एवं खाद्य कारोबारियों की जागरूकता बैठक आयोजित की गई। यह बैठक खाद्य एवं औषधि नियंत्रक, छत्तीसगढ़ तथा कलेक्टर बेमेतरा के निर्देश पर आयोजित की गई।

बैठक में जिले के होटल संचालकों, स्वीट शॉप संचालकों, डेयरी व्यवसायियों और अन्य खाद्य कारोबारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में शासन द्वारा जारी आदेशों की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा

नियमों के पालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक को संबोधित करते हुए .अभिहित अधिकारी आशीष यादव. और .वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू कुर्रे. ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में .एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध. लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि एनालॉग पनीर दूध की वसा के स्थान पर वनस्पति वसा अथवा तेल से तैयार किया जाता है। कई जगह इसे सामान्य पनीर के रूप में बेचकर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा था। ऐसे उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए जनहित में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध अवधि में किसी भी प्रकार के एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय अथवा उपयोग नहीं किया जाए। निरीक्षण के दौरान यदि किसी होटल, दुकान या प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर पाया जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध .एफएस अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक एवं विधिक कारर्वाई. की जाएगी। साथ ही कारोबारियों से असली पनीर की गुणवत्ता बनाए रखने और .ऋरअक के निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया गया।

बैठक में खाद्य अपमिश्रण की पहचान, खाद्य पदार्थों की सही लेबलिंग, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन सहित सुरक्षित खाद्य व्यवसाय संचालन पर भी विस्तृत जानकारी दी गई।

विभाग ने बताया कि जिले में समय-समय पर निरीक्षण, सैंपलिंग और जांच की कारर्वाई लगातार जारी रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। बैठक में उपस्थित होटल संचालकों, स्वीट विक्रेताओं और डेयरी संचालकों ने शासन के निर्णय का स्वागत करते हुए सभी नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

आयोजन

दुर्ग ग्रामीण में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन

जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान" रही इस वर्ष की थीम

नई दृष्टिबिंदु /दुर्ग।.

एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण. द्वारा .प्रेरणा कक्ष दुर्ग. में परियोजना स्तरीय .विश्व स्तनपान सप्ताह. का आयोजन किया गया। यह आयोजन .जिला कार्यक्रम अधिकारी आर के जाम्बुलकर. एवं .जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अजय कुमार साहू. के निर्देशानुसार किया गया। कार्यक्रम में अधिकारीगण, कमर्चारीगण, महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए .परियोजना अधिकारी उषा झा. ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी .1 अगस्त से 7 अगस्त 2026. तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष का थीम ."जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपानः कारगर उपायों को सुदृढ़ बढ़ाना". निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाना और माताओं को समर्थन प्रदान करना है। विशेष रूप से प्रसव के बाद पहले 6 माह के दौरान सहायता देना, 0-6 माह के शिशु के लिए स्तनपान की उपलब्धता बढ़ाना और शिशु एवं छोटे बच्चों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है।

मां का दूध है पहला वैक्सीन

.पयर्वेक्षक प्रमिला वर्मा. ने कहा कि मां का दूध केवल भोजन नहीं है। यह शिशु का पहला वैक्सीन है जो उसके मस्तिष्क को मजबूत बनाता है और उसे मानसिक व बौद्धिक रूप से विकसित करने के साथ संपूर्ण पोषण देता है। कार्यक्रम में कम से कम 2 साल तक स्तनपान और ऊपरी आहार के महत्व पर भी चर्चा की गई।

.बाल संरक्षण योजनाओं की दी गई जानकारी

कार्यक्रम के दौरान .आईसीपीएस की टीम. से .चंद्रप्रकाश पटेल, लोकमनी साहू, सीता कन्नौजे. उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को .दत्तक ग्रहण योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ और पॉक्सो एक्ट. के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय मे मामला क्रमांकः 202607101000246

विषयः- अ-6 अ मामले की श्रेणीः- राजस्व
सत्रः- 2025-2026
कोहका प.ह.न. 00045 [(हे0)]
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार -मोहम्मद परवीज असरफ एवं अन्य ०८,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

आवेदक - मोहम्मद परवीज असरफ एवं अन्य ०८ पिता/पति/विभाग-उबैदुल्लाह पता-फरीद नगर कोहका भिलाई के द्वारा ग्राम - कोहका प.ह.न. 45 रा.नि.म. कोहका, तहसील ०? जिला - दुर्ग की भूमि पुराना ख.न. 310/16, रकबा 3684 वगर्फीट नया खसरा न. 2577/27, 2577/26 आवेदक मो.उबैदुल्लाह एवं मो.हनीफ के नाम पर शामिलात खाते पर दर्ज था! जिसमे से मो.हनीफ ने दिनांक 23/07/1987 को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम आधी भूमि 1842 वगर्फीट भूमि को विक्रेता असगर अली आ. सत्तार को विक्रय कर दिया! जिसके पश्चात शेष रकबा पर मो.उबैदुल्लाह के नाम पर दर्ज होना था! जो त्रुटी वश खसरा न. 2577/27 में मो.हनीफ के वारिसनो का नाम दर्ज हो गया जिसे सुधार किये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है!
अतएव इस संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 14/08/2026 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयवधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27/07/2026 को जारी किया जाता है।

दिलेश्वर साहू
अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

कार्यालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छग)

व्यक्तिगत सूचना

रा०प्र०क्र० 202606101000179 / अ-6 / वर्ष 2025-26

प्रति,
हिना अंजुम पति मोहम्मद सोहेल
निवासी 135 चतुर्थ तल शिखर ग्रीन अपाटर्मेंट अपोलो हास्पिटल के पास जुनवानी रोड भिलाई तह. व जिला दुर्ग छग
एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि आवेदक लिखन देशमुख पिता/पति/विभाग-मोतीलाल देशमुख पता-भिलाई द्वारा ग्राम - कुरूद प.ह.न. 46 रा.नि.म. कोहका, तहसील ०? जिला - दुर्ग की भूमि ख.न. 177/2 का टू० रकबा 0.003 हे./367.50 वगर्फीट को आवेदक द्वारा क्रय किया जाकर ऋणपुस्तिका प्राप्त कर लिया गया है किन्तु उक्त भूमि वतर्मान पटवारी अभिलेख में आवेदक के स्थान हिना अंजुम के नाम प्रदर्शित हो रहा है! जिसे त्रुटी सुधार किये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
अतः आपको इस संबंध में यदि कोई आपत्ति एवं दावा उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक .17.08.2026 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।
आज दिनांक 23.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से प्रकाशन जारी किया गया हैं।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय तहसीलदार भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग

--:: ईश्तहार ::--

रा०प्र०क्र० अ-6 वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निसार अहमद पिता मो0 सोहराब निवासी भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प०ह०नं0 45 स्थित भूमि ख0नं० 3356 रकबा 0.020हे0 भूमि आवेदक के माता रबिया खातून पति मोहम्मद सोहराब के नाम पर दर्ज है भूमि जो कि रबिया खातून पति मोहम्मद सोहराब के नाम पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है, उक्त आवेदित भूमि के भूमिस्वामी रबिया खातून पति मोहम्मद सोहराब की मृत्यु होने से मृतक भूमिस्वामी के द्वारा मृत्यु पूर्व अपने जीवनकाल में आवेदक के नाम पर पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया था, भूमिस्वामी की मृत्यु होने पर आवेदित भूमि को पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर आवेदक स्वयं के नाम पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 18.08.2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03.08.2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

हम में से कई लोगों के बाल शैम्पू करने के बाद उलझने लगते हैं, कंघी करते वक्त इन बालों में गांठें बनने लगती है। अगर ये लगातार उलझे हुए रहने लगें तो इससे ये कमजोर होकर टूटने लगते हैं। गर्मियों में तो यह समस्या और भी ज्यादा रहने लगती है। बालों को उलझने से बचाने के लिए कंडीशनर और हेयर स्पा जैसे हेयर केयर प्रॉडक्ट से बालों को सुलझाया जाता सकता है, लेकिन नतीजे से पहले आपको इस बात की तह तक जाना बहुत जरुरी है। आखिर बाल उलझने की मूल वजह क्या है। इस वजह को जानकर आप अपने बालों को उलझने से बचा सकते हैं।

गर्मियों में क्यों बालों में पड़ जाती हैं गांठे

डिहाइड्रेशन की वजह से

गर्मियों में डिहाइड्रेशन सिर्फ शरीर में ही नहीं होती है, बल्कि ये बालों में भी होती है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो बाल भी उलझने लगते हैं। रूखे बाल आपस में बुरी तरह उलझ जाते हैं और उन्हें सुलझाना मुश्किल होता है। जब बाल अच्छी तरह हाइड्रेटेड नहीं रहते, तो बाल कमजोर और संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे वे बीच से ही टूटने लगते हैं। इसलिए नियमित रूप से बालों को कंडीशनर करें और बीच-बीच में मॉइस्चराइज़िंग हेयर मास्क का भी इस्तेमाल करें। ढेर सारा पानी और लिक्विड पिएं, ताकि शरीर के साथ आपके बाल हाइड्रेटेड रहें।

अल्कोहल युक्त शैम्पू का न करें इस्तेमाल

अल्कोहल युक्त हेयर केयर प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल न करें। इससे बालों की नमी जाने लगती है। शैम्पू, कंडिशनर से लेकर हेयर स्टाइलिंग प्रॉडक्ट्स तक में अल्कोहल मुक्त का लेबल देखकर ही प्रॉडक्ट्स खरीदें। क्योंकि अल्कोहल युक्त प्रॉडक्ट्स के नियमित इस्तेमाल से बाल रूखे और बेजान होने लगते हैं और इस वजह से बाल उलझने लगते है और गांठे बन जाती है। बालों को खुला छोड़कर सोने पर बाल खुले रखकर सोने से वे उलझ जाते है। इसलिए ढीली-ढाली चोटी बनाकर सोएं और यदि आप सहज न हों, तो शुरुआत करने के लिए ढीली पोनी बना सकती हैं। बालों की सही तरह से करें कंघी कई बार सुबह जल्दबाज़ी में हम बालों को कंघी करना भूल जाते हैं। बालों में हाथ फिराकर बाल तो थोड़े-बहुत सेट हो जाएंगे, लेकिन कंघी न करने पर बालों की सेहत जरूर बिगड़ जाएगी। लंबे समय तक कंघी न करने पर बालों में गांठ भी पड़ जाती है। दिन में कम से कम दो बार कंघी ज़रूर करें। इससे बाल जल्दी उलझेंगे नहीं। चौड़े दांतोंवाली कंघी का इस्तेमाल करें, ताकि बाल कम से कम टूटें। रात को कंघी करे बिना सोने से भी बाल उलझ सकते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले उन्हें सुलझाना न भूलें।

बालों को सही तरीके से सुखाएं

कुछ लोग बाल धोने के बाद उन्हें तेजी से रगड़ते हैं या झाड़ते हैं। यह बहुत गलत तरीका है। इससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। शैम्पू करने के बाद बालों को तौलिया से बहुत आराम से पौंछे इसके लिए किसी पतले कपड़े का इस्तेमाल करें। बालों को तौलिए से ज्यादा कस कर न बांधें। धूप में बैठकर या कूलर के सामने बाल सुखाना भी बालों को नुकसान पहुंचाता है। इससे न केवल बाल उलझते हैं, बल्कि कमजोर होकर टूटने भी लगते हैं।

नीम हकीम से बच कर रहे

एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन का आधार होता है-संतुष्ट सेक्स जीवन। लेकिन, पश्चिमी देशों के विपरीत हमारा समाज हमें प्यार को खुले तौर पर करने की इजाजत नहीं देता। सेक्स वह कला है जिसका वर्णन हमारे पूर्वजों द्वारा कई शतकों पहले कामसूत्र में भी किया जा चुका है। इससे जुड़े कई मिथ्य और भ्रांतियों ने इसे एक रुकावट बना दिया है। हालांकि शहरों मे यह चित्र तेजी से बदल रहा है। लेकिन, देश के अधिकतर भागों में ज्ञान की कमी और जानकारी के अभाव में लाखों लोग एक असंतुष्ट सेक्स जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।

नई दिल्ली स्थित अशोक क्लिनीक रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ डॉ. अशोक गुप्ता के अनुसार आज भी, नपुंसकता एक ऐसा विकार है जिसे पुरुषों में सबसे अधिक खराब और हीन माना जाता है। इसके लिए दो तत्व बहुत जिम्मेदार होते हैं। पहला, ज्ञान की कमी, अंधविश्वास, अपराधबोध आदि से लोग सेक्स जीवन में नाकामयाब होते हैं। दूसरा, झूठे झांसे और ऐसे ठग व झोलाछाप डाक्टर, जो ऐसे मरीजों को धोखा देकर उनके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे झांसे और झूठे दावा करने वाले सेक्सोलोजिस्ट मरीज की नासमझी का फायदा उठाते हुए उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर देते हैं कि वे अपनी इस समस्या जैसे इरेक्टाइल डाइसफंक्शन को छिपा कर रखें और किसी से भी इसका जिक्र न करें।

अधिकतर एंड्रोलोजिस्ट के मुताबिक नपुंसकता या इरेक्टाइल डाइसफंक्शन एक आम विकार है। कहा जाता है कि लगभग दस प्रतिशत पुरुष इससे पीड़ित हैं। 40 की उम्र के लगभग 52 प्रतिशत लोग इसका शिकार होते हैं। आज भी शर्म और नासमझी के कारण केवल कुछ ही मरीज इलाज के लिए आगे आते हैं और अधिकतर लोग डाक्टर के बजाय किसी ठग या ढोंगी के पास जाना ज्यादा उचित समझते हैं। दरअसल, किसी भी पुरुष का अहम उसे इस बात को जगजाहिर करने की इजाजत नहीं देता जिससे उसके पौरुष पर कोई सवाल उठे। डा. गुप्ता, जिन्होंने हजारों मरीजों को इस समस्या से छुटकारा दिलाया है का कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यवश है क्यों कि अगर मरीज समय रहते प्रशिक्षित और अनुभवी डाक्टर के पास चले जाएं तो अधिकतर केसों में नपुंसकता का उपचार किया जा सकता है । अगर सेक्स से संबंधित मिथ्य और नासमझी की बात की जाए तो अशोक क्लीनिक के संस्थापक डा. अशोक गुप्ता के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में किए गए एंड्रोलोजिकल शोधों से यह पता चलता है कि मात्र व्यायाम और ऐरोबिक्स की मदद से भी कई मरीज अपना खोया हुआ पौरुष प्राप्त कर सकते हैं और शादीशुदा जीवन का आनंद उठाने के बीच में छोटी-मोटी रुकावटों को भी दूर कर सकते हैं। जबकि ठग, ढोंगियों और झोलाछाप डाक्टरों को तो सबसे आखिरी विकल्प मानकर चलना चाहिए। एक नासमझ और शर्मीला व्यक्ति, जो कि ऐसे ढोंगियों और झोलाछाप डाक्टरों के पास अपनी समस्या को लेकर जाता है, उसे यही विश्वास दिलाया जाता है कि नपुंसकता की वजह साइकोलोजिकल समस्या ही है जबकि 80 से 90 प्रतिशत केसों में क्रोनिक नपुंसकता दिमाग की नहीं बल्कि शारीरिक समस्या की वजह से होता है। डा.अशोक गुप्ता के मुताबिक ऐसा इसलिए भी होता है क्यों कि थोक के भाव में उपलब्ध ठगी और ढोंगियों से अपनी समस्या का खुलासा करना ऐसे मरीजों को अधिक उपयुक्त और विकल्प दिखता है।

1998 में एसोसिएशन आफ मेडिकल कंसल्टेंट के द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि भारत में लगभग 1.5 मिलियन ठग और झोलाछाप डाक्टर हैं और मुंबई में लगभग 10,000 झोलाछाप डाक्टरों का बसेरा है। पिछले एक दशक से, यह आंकड़े 2.5 मिलियन को पार कर चुके हैं और शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि इनमें 80 प्रतिशत ठग सेक्स समस्याओं से संबंधित हैं। इन रपटों में सबसे रोमांचक बात जो सामने आई है वह यह है कि उस समय महराष्ट्र में 95,000 झोलाछाप डाक्टर थे और केवल 90,000 पंजीकृत डाक्टर। आई एम ए द्वारा किए गए शोध में यह भी पता चला कि हमारे देश में डाक्टरों से अधिक आंकड़े झोलाछाप डाक्टरों के हैं। अगर, गलती से एक झोलाछाप डाक्टर किसी भी कारण चाहे निदान या गलत उपचार के चलते एक वर्ष में एक मरीज को भी मारता है तो एक साल में लगभग 95,000 मर्डर होते हैं।

डा.अशोक गुप्ता का कहना है कि हालांकि इरेक्टाइल डाइसफंक्शन 13 वर्ष से लेकर 90 की उम्र में कभी भी हो सकता है और इसके कई कारण भी हो सकते हैं जैसे-मधुमेह, हाईपरटेंशन, हार्ट डिसीज, रेनल फेल्योर, न्यूरोलोजिकल डिसओर्डर, चोट, दवाएं आदि। लेकिन, इसके आधारभूत कारण कुछ ही होते हैं। युवाओं और कॉलेज जाने वाले छात्रों में इस समस्या के होने का अधिकतर कारण होता है-चोट लगना, जो कि पेनिस तक जाने वाली धमनियों को अवरुद्ध कर देता है। किसी दुर्घटना आदि के बाद चोट गंभीर या तेज हो सकती है, जो कि पेल्विस की हड्डियों में फ्रेक्चर भी कर सकती है। कई केसों में बचपन में लगी चोट जवानी में आकर इस बीमारी का न्योता दे देती है। जो लोग नपुंसकता को दिमाग की बीमारी समझते हैं उन लोगों के लिए काउंसलिंग और सेक्स थैरेपी कारगर हो सकती है।

साइकोलोजिकल तत्व और सेक्सुअल अज्ञानता के चलते छोटी-मोटी समस्याओं का छुटकारा कोई भी प्रशिक्षित काउंसलर कर सकता है। पॉलिसी बनाने वाले भी इन ढोंगी सेक्सोलोजिस्ट की लोकप्रियता से चिंतित होते हैं क्यों कि सरकारी हास्पिटलों में बढ़िया से बढ़िया सुविधा देने के बाद भी लोग इन झोलाछाप डाक्टरों के झांसे में आ जाते हैं। डा.अशोक गुप्ता के अनुसार, ऐसे मरीज सरकारी हास्पिटलों में जाने की बजाय ठग अप्रशिक्षित या झोलाछाप डाक्टरों के पास जाने में ज्यादा सहूलियत महसूस करते हैं। डा.अशोक गुप्ता के मुताबिक लोगों को और सरकार को इस बीमारी के प्रति अधिक जागरुक होना पड़ेगा। जिस तरह से एड्स, एचआईवी, कांडम आदि के प्रति लोगों में इतनी जानकारी पैदा की जा रही है ठीक उसी तरह इस समस्या को भी खुलते तौर पर लाना पड़ेगा और लोगों में जानकारी और जागरुकता पैदा करनी पड़ेगी।

भुतहा शहर से जाने जाता है

धनुषकोटि

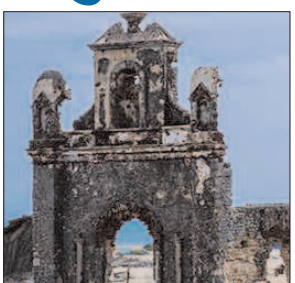

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश मे एक ऐसा शहर भी है जिसे भुतहा शहर कहा जाता है। यह शहर जिसे भुतहा कहा जाता है वहां कभी समृद्ध धार्मिक नगर था और जीवित संस्कृति सांस लेती थी। आइए आप भी जानिए हमारे साथ-साथ इसके भुतहा होने की कहानी को। रामेश्वरम से रामसेतु की ओर जाते समय ऑटोरिक्शा वाले ने कुछ खंडहरों की ओर इशारा कर बताया कि साहब ये जो खंडहर नज़र आ रहे है यहां कभी एक बड़ा अच्छा आबाद नगर था। इसे अब भुतहा शहर कहा जाता है। उसके ऐसा कहने से जिज्ञासा उत्पन्न हुई और हमने ऑटो रुकवा लिया। समुद्र के किनारे रेत पर नज़र आरहे खंडहर भवनों की ओर चल पड़े। चर्च, डिस्पेंसरी, स्कूल और कुछ अन्य भवनों के अवशेष हमारे सामने खंडहर के रूप में थे। हम जैसे ही कुछ और सैलानी भी इन्हें निहार रहे थे। कैसे होंगे ये भवन इस बारे में सभी अपने-अपने अनुमान लगा रहे थे। इनके भव्य होने की कल्पना कर रहे थे और इसकी यादों को फ़ोटो और सेल्फी लेकर अपने पास संजो रहे थे। इस से पहले समुद्री उत्तपाद शंख, सीप, मोती, मनके और इनसे बने सजावटी समान बेचने की कुछ कच्ची दुकाने सजी थी।

वहीं एक स्थानीय मछुआरे ने दूर इशारा कर बताया वहां एक रेलवे स्टेशन था। हमने जाकर देखा तो अब वहां मात्र स्टेशन भवन के खंडहर के अवशेष रहगये थे। इस क्षेत्र में आज कुछ मछुआरे रहते हैं जो समुद्र से मछली पकड़ कर उनसे अपनी आजीविका चलते है। कुछ मछुआरे रामेश्वरम से सुबह आते हैं और शाम होते होते वापस लौट जाते हैं। जहां नज़र जाती थी समुंद्र ही समुंद्र था। बताते हैं कि अंग्रेजों के समय धनुषकोटि बड़ा नगर था और रामेश्वरम एक छोटा सा गांव था। उस समय यहां से श्रीलंका के लिए नौकायें चलती थी और किसी प्रकार पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी। थलाईमन्नार-श्रीलंका जाने के लिए नाव का किराया 18 रुपये था। इसी के माध्यम से व्यापारिक लेनदेन भी होता था। वर्ष 1897 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लंका मार्ग से भारत आये तो वे धनुषकोटि भूमि पर उतरे थे। वर्ष 1964 में यह एक विख्यात पर्यटक स्थल और तीर्थस्थल था। श्रद्धालुओं के लिए यहां होटल, धर्मशालाएं, कपडो की दुकाने थीं। उस समय यहां चेन्नई से धनुषकोटि के मध्य मद्रास ऐग्मोर से बोट मेल नामक रेल सेवा संचालित होती थी। आगे श्रीलंका को फेरी बोट से जमे के लिए यह रेल सेवा उपयुक्त थी। धनुषकोटि में जलयान निर्माण केंद्र, रेलवे स्टेशन, छोटा रेलवे चिकित्सालय, पोस्ट आफिस एवं मछलीपालन जैसे सरकारी कार्यालय भी थे। धनुषकोटि जैसे समृद्ध शहर के लिए 22 दिसंबर 1964 की रात दुर्भाग्य लेकर आई जब एक भयानक समुद्री तूफान में यह नगर पूर्णतः बर्बाद हो गया। पम्बन-धनुषकोटि पैसेंजर रेल जिस में 5 कर्मचारी और 110 यात्री सवार थे प्रचंड तूफान की तरंगों की भेंट चढ़ गई। धनुषकोटि से कुछ पहने पूरी रेलगाड़ी बह गई और पूरा रेल मार्ग नष्ट हो गया। करीब 270 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आये चक्रवात से पूरा शहर खत्म हो गया। यह चक्रवात आगे रामेश्वरम तक गया उस समय भी 8 फुटट ऊँची तरंगे थी। इस परिक्षेत्र के करीब एक सहस्र से अधिक व्यक्ति काल के गाल में समा गए। कुछ लोग मारने वालों की संख्या पांच सहस्र बताते हैं। धनुषकोटि में सब कुछ खत्म होकर कुछ खंडहर रह गये। केवल एक व्यक्ति जिसका नाम कालियामन था बच गया जिसने समुद्र में तैर कर अपने प्राण बचाये। सरकार ने पास के गांव का नाम उसके नाम पर निचल कालियामन रख कर उसका गौरव बढ़ाया। धनुषकोटि बस स्टैंड के खंडहर के समीप मारने वालों की याद में एक स्मारक बनाया गया है। उस पर लिखा है-उच्च वेग से बहने वाली हवा के साथ उच्च गति के चक्रवात ने धनुषकोटि को 22 दिसंबर 1964 की आधी रात से 25 दिसंबर 1964 की शाम तक तहस नहस कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ और धनुषकोटि का पूरा शहर बर्बाद हो गया!

इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने इसे भुतहा शहर घोषित कर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। वर्षों तक यहां कोई आता जाता नहीं था। अब कुछ लोग आने जाने

मिट्टी में ही जन्में है और मिट्टी में ही वापस समाना है। तो फिर जीवन बिताने के लिए मिट्टी के घर से परहेज क्यों? सुख से जीना है तो एक अदद मिट्टी के घर का सपना देखे, संगमरमर के ताजमहल का नहीं और फिर यह बात भी अपने दिलो-दिमाग से निकाल दें कि मिट्टी या मिट्टी का घर कहते ही आपको गरीब या गरीबी का मारा समझ लिया जाएगा बल्कि मिट्टी का सच समझिए और सुखी रहिए....

आधुनिकता की भेंट चढ़ गए मिट्टी के घर

सदियों से मिट्टी के घर बनाने की जो परंपरा रही है वह कोई यूं ही नहीं चली आ रही। बल्कि आज भी यह परंपरा बखूबी जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि यह सस्ती सुलभ, टिकाऊ और अच्छी तरह आजमाई हुई सफल परंपरा है। रही बात इसके टिकाऊपन की सीमा

की तो वह तो किसी भी पदार्थ से बने घर की अपनी एक आयु होती है और इसके बाद उसका क्षय होना निश्चित है और फिर क्षय होकर इसे अंततःमिट्टी ही तो बनना है। दुनिया में सबसे ज्यादा घर मिट्टी से बने हैं। इस पर नये सिरे से सोचने की। भारत के ही संदर्भ में देखे तो लोग किसी चुम्बकीय आकर्षण से खिंचे चले जाते हैं। शहर की ओर। किसी अदृश्य बांसुरी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन ही मानों गांवों और कस्बों लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित मिट्टी ही मानी जाती है। खासकर मकान बनाने हो तो कभी कोई व्यक्ति मिट्टी के घर बनाने की बात नहीं सोचता। हरेक के जेहन में तुरंत उभरता है पक्के घर के रूप में सीमेंट, कंक्रीट से बना टाइल्स, मोजैक और संगमरमर लगा घर। जबकि इन सामग्रियों से बने घर हमेशा ही महंगे साबित हुए हैं। कई हाथों की जरूरत भी पड़ती है और फिर सीमेंट बनाने में पक्की ईंटें बनाने में पर्यावरण कितना प्रदूषित होता है। इस तथ्य को भी नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

सच्चाई तो यही है कि आज भी विश्व भर के आधे से ज्यादा आबादी मिट्टी के घरों में ही रहती है। भले ही मिट्टी के घर बनाने की निर्माण प्रक्रियाएं विभिन्न हो। अंदाजन भी देखे तो पाएंगे कि 25 मिलियन परिवारों के पास रहने को घर नहीं है जबकि विश्व के विकासशील देशों में अर्धाधिक आबादी के पास मिट्टी के घर बनाने की सोचना हीं समझदारी नहीं कहलाएगी? जरूरत है सिर्फ सच्चाई जानने की और के लोगों को शहर की ओर जाने को सम्मोहित कर देती है। जबकि यहां आकर उनको झुग्गी-झोपड़ियों वाले सर्वथा असुविधाओं भरे अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहना भी पड़ता है और वहीं काम भी करना पड़ता है। फिलहाल भारत में 290 मिलियन लोग शहरों और महानगरों में रहते हें। 1991 में महानगरों की संख्या 23 थीं जो 2001 तक बढ़कर 40 हो गई है और 2025 तक तो यह भीड़ शहरी आबादी को खचाखच भर डालेगी। इनके अलावा कोई 580,760 गांवों में तकरीबन 629 मिलियन लोग रहते हैं। यानी औसतन हिसाब लगायें तो प्रति गांव 1,083 की आबादी। अब हरेक को एक अदद छत तो चाहिए ही। कम लागते वाले घर की ही तलाश ज्यादातर लोगों को रहती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो 2021 तक शहरों में तकरीबन 77 मिलियन घरों और ग्रामीण इलाकों में 63 मिलियन घरों के निर्माण की आवश्यकता होगी। अब योजना आयोग के इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो क्या इतनी ज्यादा संख्या में सीमेंट पक्की ईंटों और इस्पात का उपयोग करके घर बनाना संभव है। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने मन-मस्तिष्क में यह सत्य बिठा लें कि मिट्टी का मोल और महत्व समझना ही बेहतर है। चाहे सुनने में यह बात पुराने फैशन जैसी ही क्यों न लगती हो। बात आसानी से हजम नहीं होती हो तब फिर इस तरह सोचें कि घर या इमारतें बनाने में यह जो लोहा, इस्पात, शीला, एल्युमिनियम, सीमेंट, संगमरमर, पक्की ईंटें वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। उन सबकी उपलब्धता के दौरान पर्यावरण में कितनी अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है और इनके लिए कितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है।

इसके अलावा जीवन के लिए सबसे पहली जरूरत समझे जाने वाले हवा और पानी में कितना जहर घुलता है। इनके विपरीत जिन भवन निर्माण सामग्रियों में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की खपत होती है वे पर्यावरण में भी कम ही प्रदूषण फैलाते हैं। मिट्टी एक ऐसी ही प्राकृतिक निर्माण सामग्री है। अब अगर मिट्टी की विशेषता जानना चाहे तो इसकी उपलब्धता से ही शुरूआत की जा सकती है। 250 वर्ग मीटर की जमीन पर 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला मकान तैयार करना है तो 60 क्युबिक मीटर मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए बेसमेंट एरिया छोड़कर 01266 मीटर (यानी साढ़े दस इंच) गहराई तक खोदकर निकाली गई मिट्टी पर्याप्त होगी। (दीवारें खड़ी करने के लिए)। सवाल यह उठ सकता है कि अगर इतने ही गुण है मिट्टी में तो फिर इससे मकान बनाना बंद क्यों हो गया? इस सवाल के जवाब में केरल की मशहूर हस्ती लॉरी बेकर का कहना है कि दरअसल जब से हमने अपना घर खुद बनाने के बजाए दूसरे लोगों पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी तब से यह पृथा गड़बड़ा गई। लॉरी बेकर कुशल मृतिका शिल्पी माने गए हैं। उनका यह भी कहना है कि भारत में हमारी मानसिकता ही ऐसी सनक का शिकार हो गई है कि मिट्टी यानी गरीब और गरीबी। सबसे पहले इस गलत धारणा को दूर करना चाहिए।

उनका मानना है कि एक मध्यम श्रेणी का ईंटों वाला साधारण सा घर बनाने के लिए मात्र दो या तीन बड़े पेड़ों को काटकर इसके जलावन से आवश्यक संख्या में ईट पकाई जा सकती है। आस्ट्रेलिया जाकर देखें कि मिट्टी से ही कैसे-कैसे कलात्मक और फैशनेबल घर बनाये गए हैं। उन्हें देखकर एक बारगी यह पता करना भी मुश्किल होता है कि ये मिट्टी से बने घर होंगे। तो दिलोदिमाग से यह फितूर निकाल दें कि मिट्टी का घर कच्चा होता है या पुराने फैशन का होता है। मिट्टी सस्ती, सुलभ और टिकाऊ भवन निर्माण सामग्री है और आप इससे नए और आधुनिक शैली के मकान भी बना सकते हैं। जो अब भी मिट्टी का लोहा मानने की कसर बाकी रह गई हो तो एक नजर इन तथ्यों पर डाल लीजिए जो संभवतः आपका रहा-सहा शक भी दूर कर दें। दरअसल ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो मिट्टी की मजबूती साबित करती है। इग्लैंड के डेवॉन कंट्री में आज भी 40 हजार मिट्टी की बनी कुटियाएं मौजूद हैं और इनमें से कई कुटिया 500 साल पुरानी है। चूने से लिपी-पुती इन कुटियाओं पर फूस के छप्पर पड़े हुए हैं। जेरिको में आपको धूप में सुखाई गई ईंटों से इमारतें देखने को मिलेगी। ये भी ईसा पूर्व आंठवीं सहस्राब्दी की बनी हुई इमारतें हैं। आग जलाकर ईंटों को सुखाने अथवा पक्की बनाने का चलन तीसरी सहस्राब्दी तक भी नहीं था, क्योंकि ईंधन जलाकर ईंट सुखाना खर्चीला समझा जाता था।

टैलेंट और पॉपुलैरिटी दोनों जरूरी, अच्छे एक्टर्स की हमेशा रहेगी डिमांड

डिजिटल दौर में मनोरंजन की दुनिया तेजी से बदल रही है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण अब फिल्मों और वेब शोज में इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री भी बढ़ती जा रही है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं, जो पहले सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित थे। ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या इससे प्रोफेशनल और ट्रेनिंग प्राप्त एक्टर्स के मौके कम हो जाएंगे। इसी मुद्दे पर टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता हितेन तेजवानी ने आईएनएस को दिए इंटरव्यू में अपनी राय रखी है। हितेन तेजवानी ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स की जगह ले सकते हैं। अगर किसी किरदार के लिए मजबूत अभिनय की जरूरत होगी तो मेकर्स उसी कलाकार को चुनेंगे जो उस रोल के साथ न्याय कर सके। एक्टिंग एक स्किल है, जिसे सीखना और समझना जरूरी होता है, और यह हर किसी के बस की बात नहीं होती।'' हितेन ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को समझाते हुए कहा, ''शूटिंग के दौरान समय की काफी कमी होती है। ऐसे में मेकर्स को ऐसे कलाकारों की जरूरत होती है, जो कम समय में बेहतर परफॉर्म कर सकें। अगर कोई प्रोजेक्ट गहरी और दमदार कहानी पर आधारित है तो उसमें अनुभवी और टैलेंटेड एक्टर्स को ही प्राथमिकता दी जाती है।''

उन्होंने कहा, ''किसी भी प्रोजेक्ट में काम करना या न करना कलाकार के अपने फैसले पर भी निर्भर करता है। हर एक्टर अपनी पसंद और स्क्रिप्ट के आधार पर प्रोजेक्ट चुनता है, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कोई एक वर्ग दूसरे का काम पूरी तरह छीन लेगा।''

हितेन ने कहा, ''इंडस्ट्री में दोनों का अपना महत्व है। अगर किसी प्रोजेक्ट में एक पॉपुलर चेहरा होता है तो उससे फिल्म या शो को ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है, लेकिन इसके साथ-साथ अच्छे और अनुभवी एक्टर्स का होना भी उतना ही जरूरी है, जो कहानी को मजबूत बना सकें।'' उन्होंने खासतौर पर थिएटर और एक्टिंग बैकग्राउंड से आने वाले कलाकारों की तारीफ की। उन्होंने कहा, ''ऐसे कलाकार अपने अनुभव और समझ से किरदार में गहराई और असलियत लेकर आते हैं, जिससे कहानी ज्यादा प्रभावशाली बनती है।''

संयुक्ता ने बताया किस एक्टर के साथ दोबारा काम करना चाहेंगी?

धनुष के साथ फिल्म 'वाथी' में अपने अभिनय से सुर्खियां बटोरने वाली अभिनेत्री संयुक्ता इस साल कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने फिर से धनुष के साथ काम करने की संभावनाओं के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने बताया कि क्यों धनुष के साथ वो काफी कंफर्टेबल महसूस करती हैं।

धनुष को बताया शानदार एक्टर

बातचीत में जब संयुक्ता से पूछा गया कि वह किस अभिनेता के साथ दोबारा काम करना चाहेंगी? इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मैं उन सभी मलयालम अभिनेताओं के साथ काम करना चाहूंगी, जिनके साथ मैंने काम किया है। साथ ही धनुष के साथ भी मैं दोबारा काम करना चाहूंगी। वह शानदार अभिनेता हैं। जब वो कोई स्क्रिप्ट चुनते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि वो अच्छी कहानी है।

अपने काम में मस्त रहते हैं धनुष

'वाथी' में धनुष के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि उनके साथ काम करना बहुत बढ़िया था। मेरा मतलब है मुझे यकीन है कि आपने इसे देखा होगा। उनके साथ एनर्जी लेवल अलग ही होता है। वो कम बोलने वाले, बेहद पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। वो अपने काम में मग्न रहते हैं। कैमरे के सामने उनका शांत स्वभाव, पर्दे पर उनकी ताकत को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपना सारा जोश कैमरे के सामने वाले उस एक पल के लिए बचाकर रखते हैं। जब निर्देशक एक्शन कहते हैं, तो वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं। वेंकी अटुलुरी द्वारा निर्देशित पीरियड एक्शन ड्रामा 'वाथी' 2023 में रिलीज हुई थी। यह उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक है।

ऐसा रहा संयुक्ता का करियर

संयुक्ता के करियर की बात करें तो उन्होंने मलयालम फिल्म 'पॉपकॉर्न' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कल्कि (2019), एडक्कड़ बटालियन 06 (2019), भीमला नायक (2022), कडुवा (2022), बिम्बिसारा (2022), गालीपाटा 2 (2022), वाथी (2023) और विरुपाक्षा (2023) जैसी कमर्शियल रूप से सफल फिल्मों में काम किया। संयुक्ता आखिरी बार 2025 में रिलीज हुई 'अखंडा 2 : थांडवम' और 'नारी नारी नादुमा मुरारी' में नजर आई थीं।

'मातृभूमि' के बाद अब मेगा एक्शन अवतार में दिखेंगे सलमान, अगली फिल्म की तैयारी शुरू

सलमान खान की आगामी फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज फिलहाल टल गई है। फिलहाल, टीम ने रिलीज की तारीख तय नहीं की है। लेकिन फिल्म के टॉपिक को देखते हुए इसे स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज करने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अब अपनी अगली बड़ी फिल्म की तैयारी में जुटने वाले हैं।

अप्रैल 2026 से शुरू होगी शूटिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान अप्रैल 2026 से निर्माता दिल राजू और डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली के साथ अपनी नई एक्शन फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। यह फिल्म एक बड़े बजट की कमर्शियल एंटरटेनर बताई जा रही है, जिसमें एक्शन के साथ इमोशन का भी तड़का देखने को मिलेगा।

ईद 2027 पर रिलीज होगी फिल्म!

खास बात यह है कि मेकर्स इस फिल्म को ईद 2027 पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे सलमान खान एक बार फिर अपने फेवरेट फेस्टिव सीजन में बड़े पर्दे पर वापसी कर सकें। फिलहाल फिल्म का प्री-प्रोडक्शन काम तेजी से चल रहा है और शूटिंग अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। यह फिल्म भारत की अलग-अलग लोकेशंस पर शूट की जा सकती है और इसमें बड़े लेवल पर वीएफएक्स का भी इस्तेमाल होगा। बताया जा रहा है कि सलमान खान इस फिल्म में एक नए अंदाज में नजर आएंगे, जिसे लेकर फैंस के बीच अभी से काफी एक्साइटमेंट है।

प्रियदर्शन के साथ काम करना सपने के सच होने जैसा

अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत-बंगला' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को यूए-16 की रेटिंग के साथ रिलीज की अनुमति मिली है। फिल्म में बंगाली एक्टर जिशु सेनगुप्ता ने भी अहम किरदार निभाया है। अब उन्होंने फिल्म में अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ काम करने को किसी सपने के सच होने जैसा बताया है।

बातचीत में जिशु सेनगुप्ता ने कहा, डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ काम करना उनके लिए सपने का सच होने जैसा है, क्योंकि जब वे सीरियस फिल्म बनाते हैं, तब सेट पर गंभीरता का पैमाना अपने आप सेट हो जाता है और जब वे कॉमेडी फिल्म बनाते हैं तो सेट पर कॉमेडी के नए आयाम स्थापित हो जाते हैं। मेरी पहली मुलाकात इनसे सीसीएल में हुई थी, जब मैंने उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि समय ज्यादा लग गया, लेकिन उनके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ सेट पर काम करने के अनुभव पर जिशु सेनगुप्ता ने कहा, 'पहले कुछ दिन अजीब लगता है, मैं नर्वस नहीं था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था क्योंकि सेट पर एक के बाद दूसरा शॉट हो रहा था और नहीं पता कि सीन में कोई कमी तो नहीं है। मैंने पूछा तो पता चला कि सब कुछ परफेक्ट है। जब सब कुछ परफेक्ट होता तो डायरेक्टर कुछ नहीं बोलते और जब कमी होती तो वे सामने से आकर बोलते थे। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर सेट पर सबकी सुनते थे। अक्षय सर कुछ बताते तो वो तुरंत मान जाते थे।'

'भूत-बंगला' के लिए 'हां' करने के सवाल पर अभिनेता ने कहा कि भले ही फिल्म में बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन हर किरदार का अपना अस्तित्व है और अलग कहानी है। मेरे लिए अच्छा किरदार बहुत मायने रखता है और यही कारण है कि मैंने फिल्म को करने के लिए 'हां' की।

हिंदी सिनेमा और बंगाली सिनेमा में बनने वाली फिल्मों पर जिशू ने कहा कि दोनों सिनेमा में पैसों का बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा, बंगाली सिनेमा में फिल्म 3 करोड़ में बन जाती है और फिल्म को शूट करने में 16-18 या 20 दिन काफी हैं, लेकिन बॉलीवुड में फिल्मों का बजट बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी फिल्म का गाना ही 10 दिन में शूट होता है, क्योंकि भव्य सेट बनाए जाते हैं। इतने में बंगाली सिनेमा में आधी फिल्म शूट हो चुकी होती है।

फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत को लेकर अभिनेता का कहना है कि वो कभी भी एक्टिंग में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता थिएटर एक्टर थे। उन्होंने कहा, 'मेरी मां नहीं चाहती थी कि मैं फिल्मों में आऊं और न ही मैं आना चाहता था। मुझे म्यूजिक ज्यादा पसंद है और खुद का बैंड भी है, लेकिन किस्मत पता नहीं कैसे सिनेमा में ले आई।' अभिनेता ने खुलासा किया कि वे कभी अपनी खुद की फिल्में नहीं देखते हैं।

कभी-कभी बोझ इतना ज्यादा होता है कि लेना पड़ता है ब्रेक, लोग पूछने लगते हैं सवाल

दिव्या दत्ता ने अपने अभिनय का जादू कुछ इस कदर लोगों के जहन में छोड़ा है कि उनका नाम ही उनकी मेहनत को बयां कर देता है। वीर जारा, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों नजर आईं दिव्या हाल ही में इंटरनैशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में शिरकत करने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने ओटीटी में महिलाओं की भूमिका पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे ओटीटी ने अभिनेत्रियों की मेहनत को दर्शकों तक पहुंचाया है।

एक लंबा दौर रहा है जब कोई फिल्म रिलीज होती थी, तो लोग पूछते थे कि ऐक्टर कौन है। इस वजह से हिराइनों के किरदार की अहमियत ढक जाती थी। लेकिन ओटीटी पर महिला प्रधान सीरीज और फिल्में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ओटीटी पर आने से क्या अब उन कलाकारों को एक संजीवनी मिली है, जो हीरो की साख में कहीं खो जाते थे? नवभारत टाइम्स के इस सवाल पर दिव्या कहती हैं, 'मुझे लगता है कि ओटीटी आज सबको मौका दे रहा है। पहले इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उस समय होता यह था कि तू भी आजा, वो भी आ जाए। एक ही किरदार आपको हर जगह दिखता था, ये ही कॉमेडी करेंगे, ये ही विलन होंगे, ये ही हीरो होंगे, लेकिन हिरोइनें बदल जाती थीं।'

टीवी एक्टर्स के लिए अच्छा समय

दिव्या ने आगे कहा, 'एक समय था जब लोग कहते थे कि टीवी के कलाकार फिल्मों में नहीं आ सकते और जो छोटे रोल करते हैं वो बड़े रोल नहीं कर सकते। अब वो लाइन खत्म हो गई है। अब अगर आप अच्छे हैं और आप उस रोल को सूट करते हैं तो आप हैं। और यह ऐक्टर के साथ बहुत ही बेहतरीन बात हुई है। इसका क्रेडिट मैं दर्शकों को दूंगी।'

ब्रेक लेती हूं तो लोग पूछते हैं सब ठीक है?

लंबे करियर के बीच काम से ब्रेक लेना कितना जरूरी है, इस पर दिव्या कहती हैं, 'आपको काम से ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती ही है। एक समय ऐसा भी आया था, जब मैंने पांच महीने का ब्रेक लिया था। क्योंकि कभी-कभी काम का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको आराम की जरूरत महसूस होती है। उस समय हर कोई मुझसे पूछता था कि क्या मैं अपने घर पर ठीक हूं? लोग कहते थे कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना-जुलना चाहिए। लेकिन जब आपकी कोई फिल्म रिलीज होती है और वह फिल्म अच्छी होती है, तो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं।'

ओटीटी कॉन्टेंट स्टार्स नहीं कहानी की जरूरत देखता है

ओटीटी पर आज बड़े स्टार्स से लेकर नए कलाकार तक नजर आते हैं। लेकिन दिव्या का कहना है कि ओटीटी लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है, यहां जो जिस काबिल है, उसे वो ही मिलता है, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो। वह कहती हैं, 'आज कई लोग कहते हैं, धुरंधर आई है तो उसका एक्शन तो हम बड़े पर्दे पर ही देखेंगे। लेकिन सब फिल्में उतनी अच्छी नहीं चलतीं, उन्हें उतना वक्त नहीं मिलता है। जैसे होता था कि फलाना हीरो होगा या हिरोइन होगी तो ही फिल्म पर्दे पर लगेगी, ओटीटी पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। ओटीटी पर आप स्टार्स को भी देखेंगे लेकिन उन रोल में जो उन्हें सूट करते हैं। अगर जबरदस्ती का कोई किरदार उन्हें दिया जाता है तो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। यह एक बहुत लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है। चाहे आप नए हों या जाने-माने ऐक्टर हों या कोई बड़े स्टार हों, अगर आप उस शो में हैं तो इसलिए हैं क्योंकि आप उस रोल से जुड़े हुए हो। वरना दर्शक निर्णय करते हैं कि फलाना शो नहीं देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि उन्होंने किसको नकारा है।'

'विधायक निधि से 5-5 लाख देने का वादा झूठा' वैशाली नगर विधायक के खिलाफ 'आप' ने खोला मोर्चा

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी ने रिकेश सेन पर लगाए गंभीर आरोप

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई।

आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग ने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन. पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए गुरुवार को सुपेला स्थित नेहरू भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी नेताओं ने कहा कि विधायक द्वारा विधायक निधि से समाजों को राशि देने की घोषणा महज एक जुमला साबित हुई है।

2 साल बाद भी नहीं मिली विधायक निधि की राशि

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 'आप' पदाधिकारियों ने बताया कि .09 अगस्त 2024. को विधायक रिकेश सेन ने समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर घोषणा की थी कि वे अपनी विधायक निधि से वैशाली नगर के .सभी 68 समाजों. को सामाजिक भवन निर्माण के लिए .5-5 लाख रुपये. देंगे। कुल .3.40 करोड़ रुपये. की यह घोषणा की गई थी। लेकिन आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी समाज को यह राशि नहीं मिली। फ्ळक से मिली जानकारी के हवाले से नेताओं ने कहा कि विधायक निधि में 68 समाजों को 5-5 लाख देने का कोई उल्लेख या प्रावधान ही नहीं है।

पार्टी नेताओं ने कहा कि वैशाली नगर की जनता या समाजों ने यह मांग नहीं की थी। विधायक ने अपने जन्मदिन पर वाहवाही लूटने के लिए खुद यह घोषणा की थी। यह 2.5 लाख मतदाताओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। 'आप' ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले आंगनवाड़ी मितानी कार्यकर्ताओं को स्कूटी देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। जिस तरह केंद्र सरकार ने 15 लाख का जुमला दिया था, उसी तर्ज पर स्थानीय स्तर पर भी जनता को धोखा दिया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी ने विधायक रिकेश सेन से सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने की मांग की कि विधायक निधि से स्वीकृत राशि कब जारी होगी। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द राशि नहीं दी गई और वादे पूरे नहीं हुए तो जनता के हक के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में .जसप्रीत सिंह, के. ज्योति, मेहरबान सिंह, अविनाश, सूरज, देवेंद्र, नीतू, रामपाल, हरचरण, बलविंदर. सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

विधायक रिकेश सेनः अधिकांश समाजों को मिल चुकी है भवन निर्माण की राशि

भिलाई नगर। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन . ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि विधायक निधि से समाजों के लिए की गई घोषणा के तहत अधिकांश समाजों को राशि स्वीकृत कर दी गई है। गुरुवार को भिलाई नगर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सेन ने बताया कि .अगस्त 2024 . में उन्होंने क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न समाजों को विधायक निधि से .भवन निर्माण हेतु 5-5 लाख रुपये . देने की घोषणा की थी। विधायक ने कहा कि घोषणा के बाद बीते 2 वर्षों में चिन्हांकित अधिकांश समाजों को सामुदायिक भवन के लिए विधायक निधि से .10 लाख से 20 लाख रुपये तक . की राशि दी जा चुकी है। यह राशि 5 लाख से अधिक है। श्री सेन ने कहा कि जिन कुछेक समाजों को अभी राशि नहीं मिल पाई है, उसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं :

समाज के पास अपनी जमीन नहीं है . जमीन को लेकर विवाद है .समाज के लोग विधायक कार्यालय में संपर्क नहीं कर पाए हैं . उन्होंने अपील की कि जिन समाजों को अभी तक राशि नहीं मिली है, वे विधायक कार्यालय आकर संपर्क करें। प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

.'ढाई साल का कार्यकाल और 8 करोड़ निधि शेष' .

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि उनका कार्यकाल अभी .ढाई साल शेष . है और उनके पास लगभग .8 करोड़ रुपये . की विधायक निधि बची हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के विकास और समाजों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

138 करोड़ की लागत से नांदघाट मुंगेली रोड बनेगा फोरलेन

टू-लेन से अपग्रेड के लिए राज्य सरकार ने मंजूर किए 21.81 करोड़

नई दृष्टिबिंदु /रायपुर।

राज्य सरकार ने बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालयतक जाने वाले मार्ग को फोरलेन में बदलने का फैसला लिया है। इसके लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है। लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने वर्ष 2024 में सी.आर.आई.एफ. योजना के अंतर्गत नांदघाट-मुंगेली मार्ग के टू-लेन निर्माण के लिए 116 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने इस सड़क को फोरलेन बनाने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर राज्य शासन ने गुरुवार को टू-लेन से फोरलेन में उन्नयन के लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर दी।

36.40 किमी सड़क पर होगा काम

अब पूर्व में स्वीकृत 116 करोड़ और नई स्वीकृत 21 करोड़ 81 लाख रुपए को मिलाकर कुल 137 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से नांदघाट और मुंगेली के बीच 36.40 किमी लंबी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा।

क्षेत्रवासी लंबे समय से नांदघाट-मुंगेली मार्ग को फोरलेन करने की मांग कर रहे थे। सड़क के फोरलेन होने से मुंगेली, लोरमी, पंडरिया और मध्यप्रदेश से रायपुर आने-जाने वाले लोगों को तेज, सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री तथा नवागढ़ विधायक दयालदास बघेल ने इस स्वीकृति पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार जताते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी है।

न्यू खुर्सीपार : सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को मिली साइकिलें

नई दृष्टिबिंदु / भिलाईनगर

न्यू खुर्सीपार. स्थित .स्वामी आत्मानंद शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यालय. में गुरुवार को कक्षा 9वीं की छात्राओं को .सरस्वती साइकिल योजना. के अंतर्गत साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में .शाला विकास समिति के अध्यक्ष निर्मल साहू, संरक्षक अनिल सोनी, दीपक पांचाल, मनीष अग्रवाल. तथा विद्यालय की .प्राचार्य प्रीति गुप्ता. विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

अतिथियों ने छात्राओं को साइकिलें प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने और मेहनत से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी किया गया। सरस्वती साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को घर से विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को नियमित रूप से स्कूल पहुंचने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक, पालक और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थीं।

एनडीएमए एवं एनडीआरएफ की संयुक्त बैठक हुई

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर।

छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सीजीएसडीएमए) में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने बैठक में राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, मानसून अवधि की तैयारियों तथा आपदा प्रतिक्रिया तंत्र की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली एवं भूस्खलन जैसी मौसमी आपदाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में राज्य एवं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की कार्यप्रणाली तथा समन्वय व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं जिला प्रशासन के मध्य त्वरित प्रतिक्रिया एवं समन्वय को और सुदृढ़ बनाने पर विचार किया गया। इसी तरह पूर्व चेतावनी प्रणाली 'सचेत' प्लेटफॉर्म एवं सेल ब्रॉडकास्ट आधारित अलर्ट प्रणाली के प्रभावी उपयोग की भी समीक्षा की गई। एनडीएमए के संयुक्त सलाहकार संजीव सही ने राज्य में किए जा रहे आपदा प्रबंधन कार्यों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग पर प्रकाश डाला।

मॉक एक्सरसाइज और क्षमता निर्माण पर जोर

बैठक में मॉक एक्सरसाइज, क्षमता निर्माण, सामुदायिक जागरूकता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। आगामी मानसून अवधि के दौरान संवेदनशील जिलों में बेहतर समन्वय एवं त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने, पूर्व तैयारी को मजबूत करने तथा किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के